WWW.Kanchanujala.in

हिन्दी दैनिक

kanchanujala14@gmail.com

कंचन उजाला

लखनऊ से प्रकाशित

सच्चाई के साथ

विपाशा के ब्रेक लेने वजह

वर्षः 01 अंक : 240

लखनऊ, गुरुवार, 20 अगस्त, 2020

पृष्ठ- 6

मूल्य - 1 रुपये

प्रदेश सरकार सभी कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिये प्रतिबद्धः योगी

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्रदेश सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखा जाए। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों को कोविड-19 के उपचार के सम्बन्ध में 3 से 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में इस धनराशि से कोविड-19 के उपचार की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मेडिकल कॉलेज अपने बजट से कोविड-19 के उपचार सम्बन्धी औषधियां एवं अन्य आवश्यक सामग्री क्रय करें। मेडिकल कॉलेज को

उपलब्ध कराई गई धनराशि का पूरा उपयोग मरीजों के बेहतर इलाज पर किया जाए।

इस कार्य में यदि उदासीनता बरती गई तो सम्बन्धित प्रिंसिपल की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दशा में दवा के अभाव में मरीज का इलाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने 40 लाख 75 हजार से अधिक टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग गतिविधियों को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 80 हजार रैपिड एन्टीजन टेस्ट तथा आरटीपीसीआर विधि से 45 हजार टेस्ट प्रतिदिन करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के कार्य को और तेज किए जाने पर बल दिया। योगी ने कहा कि इसके माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट टेस्ट होने चाहिये। कोविड चिकित्सालयों में पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था होनी चाहिये। बेड की संख्या में वृद्धि इस प्रकार की जाए, जिससे सरप्लस बेड भी उपलब्ध हो सकें।

285 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य निर्धारित

नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020 ..21 के लिए गन्ना का मूल्य 285 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार को हुयी बैठक में 10 प्रतिशत तक चीनी तैयार करने वाले गन्ने का (रिकवरी रेट) लाभकारी मूल्य 285 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । जिस गन्ने से 9.5 प्रतिशत चीनी तैयार होगा उसका मूल्य 270 रुपये प्रति क्विंटल होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाता सम्मेलन में बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि जिस गन्ने का रिकवरी दर 11 प्रतिशत होगा उसका मूल्य साढे 28 रुपये प्रति क्विंटल अधिक होगा। उन्होंने बताया कि लाभकारी गन्ना मूल्य घोषित किये जाने का लाभ करीब एक करोड़ किसानों को होगा।

नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयारः राजनाथ सिंह

नयी दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विश्वास व्यक्त किया कि नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर वह अपने समुद्री जहाजों और विमानों की कार्रवाई के लिए तुरंत तैनाती कर सकती है। श्री सिंह ने यहां नौसेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के समय नौसेना ने अपने लोगों को स्वदेश लाने के लिए सबसे बड़ा अभियान 'ऑपरेशन समुद्र सेतु' चलाकर राष्ट्र के हितों की रक्षा में योगदान दिया। नौसेना ने कोरोना की चुनौती और समुद्र की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद पड़ोसी देशों से 4000 लोगों को उनके परिवारों से मिलाया। इसके अलावा मालदीव , मारिशस और मेडागास्कर जैसे देशों को मिशन सागर के जरिये चिकित्सा सहायता भी पहुंचायी। नौसेना के कोरोना महामारी के मद्देनजर क्वारंटीन केन्द्रों का भी सफलतापूर्वक संचालन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि नौसेना ने सरकार की क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास से

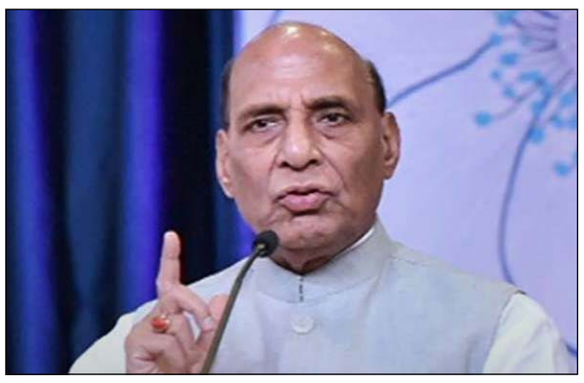

संबंधित महत्वाकांक्षी सोच 'सागर' के तहत अनेक मिशन आधारित तैनाती की और संवेदनशील स्थानों पर युद्धपोतों तथा विमानों को तैनात कर देश के समुद्री हितों की रक्षा की। इस तरह की तैनाती से नौसेना ने जरूरत पड़ने पर हिन्द महासागर क्षेत्र में मानवीय सहायता और बचाव अभियान चलाये तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा पहुंचाने में योगदान दिया। सशस्त्र बलों में हो रहे गतिशील बदलावों का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ के पद और सैन्य मामलों के विभाग के गठन का जिक्र किया। इस कदम को मील का पत्थर बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे तीनों सेनाओं में तालमेल बढेगा और विशेष रूप से प्रशिक्षण , रक्षा खरीद तथा सेनाओं में एकीकरण तथा अभियानों में इसका फायदा होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की चुनौती को स्वीकार करते हुए नौसेना ने मौजूदा वित्त वर्ष में संचालन, प्रशासन और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की है।

एक दिन में रिकॉर्ड 60 हजार से अधिक कोरोनामुक्त, सक्रिय मामले बढ़े

नयी दिल्ली, एजेंसी। देश में कोरोना महामारी से मुक्त होने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान पहली बार 60 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं हालांकि संक्रमितों की संख्या में बड़ी वृद्धि के कारण सक्रिय मामले बढ़े हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 60,091 लोगों को संक्रमण से छुटकारा मिला है जिससे स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 20,37,871 हो गयी है हालांकि इस दौरान संक्रमण के 64,531 नये मामले सामने आने से सक्रिय मामले 3,348 बढ़ गये। देश में संक्रमितों की संख्या 27,67,274 हो गयी है तथा सक्रिय मामले 6,76,514 हो गये हैं। देशभर में पिछले 24 घंटों के दौरान 1092 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 52,889 हो गयी। सक्रिय मामले 24.45 प्रतिशत, रोगमुक्त होने वालों की दर 73.64 प्रतिशत और मृतकों की दर 1.91 प्रतिशत है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 1341 बढ़कर 1,56,920 हो गयी तथा 422 लोगों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 20,687 हो गया। इस दौरान 9356 लोग संक्रमणमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,37,870 हो गयी। देश में सर्वाधिक सक्रिय मामले इसी राज्य में हैं। आंध्र प्रदेश में मरीजों की संख्या 353 बढ़ने से सक्रिय मामले 85,130 हो गये।

सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाला आरोपी गिरफ्तार

फरीदाबाद, एजेंसी। अभिनेता सलमान खान की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एसजीएम नगर में सरकारी राशन डिपो चलाने वाले प्रवीण की हत्या मामले में गिरफ्तार राहुल उर्फ सांगा नाम के इस शख्स ने मुंबई में रहकर सलमान खान की रेकी की थी। डीसीपी (मुख्यालय) राजेश दुग्गल ने बताया कि राहुल को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया, ''राहुल कुख्यात बदमाश लारेंस बिश्नोई गिरोह का शार्प शूटर है। बिश्नोई फिलहाल जोधपुर, राजस्थान की जेल में है। डीसीपी ने बताया, ''राहुल ने सलमान खान की रेकी कर, पूरी जानकारी बिश्नोई तक पहुंचाई थी। जोधपुर काला हिरण हत्याकांड से सलमान के बरी होने के कारण बिश्नोई दुखी था और वह अभिनेता से रंजिश रखता है।

सरकारी नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेन्सी का गठन

नयी दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने गैर राजपत्रित पदों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार करते हुए राष्ट्रीय भर्ती एजेन्सी (एनआरए) का गठन करने का निर्णय लिया है जो इन नौकरियों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केन्द्रीय कार्मिक और पेंशन मामलों के मंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार-युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए क्रांतिकारी और रोजगार के क्षेत्र में

ऐतिहासिक सुधार किया है। इससे भर्ती , चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जायेगी। उन्होंने कहा कि इससे निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फायदा होगा। सरकार ने एनआरए के लिए 1517.57 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। यह राशि तीन वर्ष के लिए स्वीकृत की गयी है। इस राशि का इस्तेमाल एनआरए के गठन के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा अवसंरचना को स्थापित करने के लिए किया जायेगा। अभी एनआरए गैर-तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक (12वीं पास) और मैट्रिक (10वीं पास) उम्मीदवारों के लिए अलग से संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) का संचालन करेगा। अभी इन पदों पर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा भर्ती की जाती है। सीईटी के अंक स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर, भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टियर परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा।

बिहार में कोरोना का संक्रमण,फिर भी सरकार चुनाव कराने पर अमादा

बक्सर, एजेंसी। बदलो बिहार-बनाओ बेहतर बिहार कार्यक्रम के तहत यूडीए संयोजक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बक्सर अतिथि गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में कोरोना का संक्रमण है। फिर भी सरकार चुनाव कराने पर अमादा है। संक्रमण के समय यदि चुनाव होता है तो हर मतदान केंद्र संक्रमण केंद्र बन जायेगा। चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग की गयी है। लेकिन, चुनाव आयोग अब निष्क्रिय हो चुका है। सब कुछ गृहमंत्री और सरकार तय कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का फैसला अजीबोगरीब है। छह सितंबर तक किसी भी तरह का चुनावी कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन राज्य में चुनाव समय पर होगा। उन्होंने कहा कि वर्चुअल कार्यक्रम पैसेवालों के लिए है। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से नेता अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं।

आगराः भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबे 3 लोग

आगरा, एजेंसी। उत्तर प्रदेश स्थित ताजनगरी आगरा में बैठे-बिठाए कुछ लोगों पर आफ्त आ पड़ी। जहां एक मकान भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से मलबे में तीन लोग दब गए हैं। मकान की गिरने की भयंकर आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और मामले की जानकारी अधिकारियों को दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी है। बता दें कि मामला थाना मंटोला क्षेत्र के ढोली खार का है। जहां एक मकान भरभराकर अचानक से गिर पड़ा। घटना की जानकारी होते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मलबे के नीचे दबे तीनों लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। मलबा हटाने का काम जारी है।

केंद्र सरकार ने लिया फैसला

जम्मू-कश्मीर से वापस बुलाए जाएंगे अर्धसैनिक बलों के 10 हजार जवान

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से अर्धसैनिक बलों के लगभग 10,000 जवानों को तत्काल वापस बुलाने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि कुल 100 सीएपीएफ कंपनियों को तत्काल वापस बुलाने और देश में उनके दूसरे स्थानों पर वापस जाने का आदेश दिया गया है, जहां से उन्हें जम्मू-कश्मीर में पिछले साल अनुछेद-370 के हटाए जाने के समय पोस्ट किया गया था। निर्देशों के अनुसार, इस सप्ताह तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

(सीआरपीएफ) की कुल 40 कंपनियां और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल की 20 कंपनियां जम्मू-कश्मीर से वापस बुला ली जाएंगी। एक सीएपीएफ कंपनी में लगभग 100 जवान होते हैं। गृह मंत्रालय ने मई में जम्मू-कश्मीर से लगभग 10 सीएपीएफ कंपनियों को वापस ले लिया था। अब सीआरपीएफ के पास कश्मीर घाटी में लगभग 60 बटालियन (प्रत्येक बटालियन में लगभग 1,000 जवान) होंगे। गौरतलब है कि पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुछेद-370 को हटा दिया था।

इकबाल अंसारी बोले मिली जमीन पर बाबर के नाम से कुछ नहीं बने

अयोध्या, एजेंसी। रामजन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक के विवाद में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मिली 5 एकड़ जमीन पर बाबर के नाम से कोई निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबर का इस देश से कोई भी संबंध नहीं है लिहाजा उसके नाम से कोई भी निर्माण नहीं कराया जाना चाहिए। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए मिली पांच एकड़ भूमि पर बनने वाले अस्पताल या स्कूल का नाम भारतीय मुस्लिम महापुरुषों के नाम से हो तो ज्यादा अच्छा है। यहां होने वाले निर्माण का नामकरण एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, असफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद के नाम से होना चाहिये जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। हिंदुस्तान का गौरव इन लोगों से ही है।

तीन और हवाई अड्डों का परिचालन अडाणी को सौंपने पर मंत्रिमंडल की मुहर

नयी दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम् हवाई अड्डों का परिचालन अडाणी समूह को सौंपने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को यहाँ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम् हवाई अड्डों का परिचालन निजी कंपनियों को सौंपने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इससे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीनस्थ कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को एकमुश्त 1,070 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। साथ ही यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी सुधार होगा। श्री जावडेकर ने बताया कि सार्वजनिक जन भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर लीज

पर इन हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन, रखरखाव और विकास आदि का अधिकार अडाणी समूह को सौंपा जायेगा। यह लीज 50 साल के लिए होगा। अभी इन तीनों हवाई अड्डों का परिचालन एएआई के पास है। लखनऊ, अहमदाबाद और मेंगलुरु हवाई अड्डों के साथ जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम् हवाई अड्डों को लीज पर देने के लिए दिसंबर 2018 में प्रस्ताव अनुरोध जारी किये गये थे। इनमें लखनऊ, अहमदाबाद और मेंगलुरु हवाई अड्डों के लिए अडाणी समूह के साथ एएआई ने रियायत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सीबीआई से सुशांत मामले की सही जांच की उम्मीदः कांग्रेस

नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केंद्रीय जांच ब्यूरो-सीबीआई पर भरोसा नही करते है इसलिए ज्यादा अच्छा रहता कि अभिनेता सुशांत सिंह मामले की जांच उच्चतम न्यायालय की देख रेख में होती। कांग्रेस प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिल ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री मोदी ने पहले क्ई बार सीबीआई को सरकार का तोता बताया है और उसकी जांच में वही निकलता है जो सरकार चाहती है इसलिए इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय की देख रेख में होती तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले को बिहार सरकार ने सही तरीके से नहीं रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुम्बई पुलिस की आलोचना करती रही लेकिनउच्चतम न्यायालय ने उसे सही ठहराया है इसलिए भजपा नेताओ को आलोचना के लिए माफी मांगनी चाहिए। प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले की सही जांच होनी चाहिए और उम्मीद जतायी कि सीबीआई मामले की सही जांच करेगी।

रेलवे के अंडर ब्रिज में भरा पानी, एक दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूटा

हमीरपुर, एजेंसी। जनपद में रेलवे के बने अंडर ब्रिज में पानी भरने से ग्रामीणों व राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं । 1 दर्जन से अधिक गांवो को संपर्क में जोड़ने वाला यह मार्ग पुण्यता हुआ ठप हो गया हैं। गांव वालों को आने जाने में पानी से निकल कर जाना पड़ता हैं। ये रेलवे अंडर ब्रिज मौदहा के सिजनौडा व करहिया गांव के गेट नंबर 13,14 का हैं। जहां ग्रामीणों के हालात बद से बत्तर हो गए है लोग रेलवे अंउर ब्रिज में भेरे पानी में आने जाने को मजबूर है। वही गांव वालों का कहना हैं कि ये कोई नई बात नही यहां तो हमेशा इसी तरह जलभराव रहता है। जिससे यहां के आसपास के 1 दर्जन से अधिक गांवो का संपर्क पूर्णता टूट जाता हैं। बता दें मामला हमीरपुर के मौदहा तहसील के ग्राम करहिया और सिजनौडा का हैं।

लालू के समधी चंद्रिका राय समेत तीन विधायक कल जेडीयू में होंगे शामिल

पटना, एजेंसी। लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय समेत राजद के तीन विधायक गुरुवार को जदयू में शामिल होंगे। इनमें राम लखन सिंह यादव के पौत्र और पालीगंज के विधायक जयवर्द्धन यादव तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के बेटे विधायक फराज फातमी शामिल हैं। फराज को राजद ने महेश्वर यादव और प्रेमा चौधरी के साथ पहले ही अपनी पार्टी से निकाल दिया है। फराज फातमी भी महेश्वर और प्रेमा चौधरी के साथ ही जदयू में शामिल होने वाले थे, लेकिन दो दिन पहले आयोजित मिलन समारोह में दिल्ली में होने के कारण वे शामिल नहीं हो पाए। जानकारी के मुताबिक जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव गुरुवार की दोपहर ढाई बजे प्रदेश जदयू मुख्यालय में इन तीनों को दल में शामिल करायेंगे। बहरहाल जदयू नेता दारोगा राय और रामलखन सिंह यादव, इन दो नामचीन यादव परिवारों के विधायकों के जदयू में शामिल कराने के अवसर को खास मान रहे हैं। दुंदुभी अभी बजी नहीं है, लेकिन चुनावी रेस में उतरने वाले कई घोड़ों ने अस्तबल बदलना शुरू कर दिया है। दूसरे दलों से राजद में आने वालों की संख्या अभी अधिक है, लेकिन जाने वालों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विधान सभा चुनाव के ठीक पहले तो राजद में आने की शुरुआत पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कर दी।

गोण्डा में बरसाती पानी से भरे गड्ढे में गिरने से दो बच्चों की डूबने से मृत्यु

गोण्डा, एजेंसी। उत्तर प्रदेश में गोण्डा जिले के धानेपुर क्षेत्र में बरसाती पानी से भरे गड्ढे में गिरने के कारण दो बच्चों की डूबने से आज मृत्यु हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मेहनौन गांव के प्रधान रामू सिंह ने मंगलवार को बताया कि गांव के रहने वाले पवन (12) और 13 वर्षीय वंशाराम दोपहर में गांव में ही लगे तिन्नी के चावल की बिक्री त्योहारों में करने के लिये फसल काट रहे थे। अचानक लबालब भरे गड्ढे में पवन गिर गया और उसे बचाने के लिए वंशाराम भी गड्ढे में कूद गया। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गयी। आसपास के लोगों के शोर मचाने पर ग्रामीणों नें शवों को बाहर निकलवाकर परिजनों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि पंचनामे के बाद परिजनों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया।

कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के मद्देनजर विधायकों के गनर और अन्य कर्मचारियों कोरोना परीक्षण के लिए नमूना लेते मेडिकल कर्मचारी।

लखनऊ लालबाग स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय के पास से लगाया गया बैरी कटिंग से नागरिकों को दिक्कतें वा जाम का सामना करना पड़ा।

बड़े भाई की हत्या कर शव के पास तंत्र मंत्र की साधना करता रहा युवक

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में अंधविश्वास और सनक की सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अज्ञानता और अंधविश्वास के चलते एक युवक ने बड़े को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना मंगलवार को इटौजा थाना क्षेत्र स्थित उसरना गांव में हुई है। जहां तंत्र मंत्र के चलते छोटे भाई फूलचंद रावत ने बड़े भाई बृजेश (25) को मार डाला। बड़े भाई की मौत के बाद उसका शव चार दिन तक घर में छिपाए रहा। उसने कहा कि सात दिन में तंत्र क्रिया से वह भाई को जीवित कर लेगा। कई दिन बीतने के बाद मकान से दुर्गंध आना शुरू हो गया। जिसका संज्ञान लेते पड़ोसियों ने घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, और घर का दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। जिसके बाद शव की पोस्टमार्टम के लिए भेजा और छोटे भाई को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक बृजेश की पत्नी और तीन बच्चों, उसके तीन भाइयों तथा मां से पूछताछ की गई है। परिवार के मुताबिक बृजेश रावत की मौत चार दिन पहले बीमारी से हुई थी। छोटे भाई फूलचंद ने घरवालों से कहा था कि वो बृजेश को सात दिन में जिंदा कर देगा। उसने घर वालों को धमकाया कि अगर किसी ने उसकी तंत्र क्रिया में बाधा डाली तो उसका नाश हो जाएगा। इसके बाद वह शव को लेकर घर के एक कमरे में बंद होकर साधना करता रहा। मृतक बृजेश की पत्नी न बताया कि उसका देवर शिवलिंग की प्राप्ति को लेकर पिछले 5 दिनों से घर में ही तंत्र-मंत्र कर रहा था। परिवार में मौजूद महिलाएं और बच्चों को भी डरा धमका कर घर में बंद कर दिया था। पुलिस को पड़ोसियों ने बताया, कि जब बृजेश और फूलचंद्र बारे में पूछा तो परिवार के लोग हड़बड़ा गए। बुधवार को घर से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर फूलचंद्र ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के अंदर बृजेश का शव पड़ा था और फूलचंद्र उसी के बगल में तंत्र साधना कर रहा था। जिसके बाद पुलिस ने फूलचंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पड़ोसियों ने बताया, कि दोनों भाई कई साल से इकट्ठा तंत्र-मंत्र जैसी क्रियाएं करते थे। वहीं पुलिस फूलचंद से पूछताछ कर रही है, लेकिन वह बहकी-बहकी बातें कर रहा है। उसका कहना है कि वह सातवें दिन अपनी तांत्रिक साधना से भाई को जीवित देता, इसलिए तंत्र क्रिया कर रहा था।

लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अपराधों पर रासुका के तहत सख्ती से कार्यवाही की जायः योगी

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे अपराध जिनसे लोक व्यवस्था प्रभावित हो उनमें प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कडी विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं, ताकि अपराधियों में भय एवं जनता में सुरक्षा का भाव सुदृढ़ हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध जघन्य अपराध, गोकशी की घटनाओं, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों, गम्भीर अपराधों एवं अन्य सनसनी खेज अपराधों से जुड़े अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध भा0द0वि0 की सुसंगत धाराओं के आलावा रासुका के तहत भी कार्यवाही की गयी है। शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों एवं जिले के पुलिस कप्तानों को इस बात के कड़े निर्देश दिये गये हैं कि रासुका की कार्यवाही हेतु पात्र कोई भी अपराधी बचने न पाये। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने हेतु प्रदेश मे इस वर्ष जनवरी से अब तक कुल 139 अभियुक्तो के विरूद्ध रासुका में भी कार्यवाही की गयी है। इनमें से गोकशी के अंतर्गत 76 अभियुक्तों, बालिकाओं के विरुद्ध अपराध मे 06 अभियुक्तों, गंभीर अपराध मे 37 अभियुक्तों व अन्य अपराधों में 20 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही हुई है। उक्त कार्यवाही से बड़े-बड़े शातिर अपराधियों के हौसले पस्त हुये हैं और सरकार के प्रति जनता का विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है।

विकास के बहाने नहीं, राम भरोसे है भाजपा सरकारः आफाक

लखनऊ, संवाददाता। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संयोजक मुहम्मद आफाक ने अपने एक ब्यान में लखनऊ अब्बास बाग के मैनेजर मुहम्मद हुसैन के साथ संयुक्त रूप से मुहम्मद आफाक के साथ कहा कि 6 वर्ष पूर्व होने पर भजपा सरकार ने जनता में अफरा तफरी का माहौल जो पैदा किया है, घोषणा पत्र के अनुसार बे रोजगारों को रोजगार, पंद्रह लाख हर व्यक्ति के खाते में, चीन जैसी विदेशी जो ताकतें जो हमारे हिन्दुस्तान को आँख दिखाती हैं उनसे सख्ती से निपटा जायेगा, हर व्यक्ति धन धरती, शिक्षा, स्वास्थ, सम्मान जैसी मुख्य धारा से काम किया जायेगा। बदले में भारत के प्रधान मंत्री हाहाकार मचा के विदेशी दौरे करके पांच हजार करोड़ खर्च कर डाले, देश में बेरोजगारी के लिए पांच फैक्ट्री न लगायी, बल्कि जो फैक्ट्रियां चल रही थीं उन्हें भी बंद क्र दिया, तीन हजार करोड़ का बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवा दी और क्षात्रों के लिए पांच विद्दयालय भी नहीं बनवाएं नोट बंदी जी एस टी लगाकर जनता को बेरोजगार कर दिया, अरबों रुपया लोग विदेश लेकर भाग गए, आडवाणी, अम्बानी जैसे लोगों को दिवालिया के बहाने कर्ज माफ कर दिया। कोरोना के बहाने प्रधान मंत्री ने अपने खाते में लगभग एक अरब रुपया जमा करा लिया और उसका हिसाब मांगने पर इंकार किया गया। उन्होंने ने जनता को मुर्ख बना कर ताली थाली और मोमबत्ती, राम मंदिर का शिला न्यास करके करोड़ों रूपये की वसूली की जा रही है, अंत में मुहम्मद आफाक ने कहा कि मुझे तो दर है कि कहीं राम मंदिर के नाम पर दान के बारे में किसी ने पूछ लिया तो मोदी, योगी और उनकी कमेटी देश द्रोह का कहीं मुकदमा न दर्ज करा दें, पुरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ राम भरोसे मोदी सरकार चल रही है, और यह मस्सगे देना चाहती है कि मुस्लिम इस देश में बहुत ताकतवर है और उनसे तुमको संघी विचार धारा और बी जे पी के लोग ही बचा सकते हैं, जबकि सदियों से हिन्दू मुस्लमान एक साथ रहते चले आ रहे हैं।

आगरा बस हाईजैक मामले में सीएम योगी सख्त, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश

लखनऊ, संवाददाता। यूपी के आगरा बस हाइजैक मामले में बड़ी जानकारी मिली है। आगरा जिले में न्यू दक्षिणी बाइपास पर मंगलवार रात हथियारों से लैस बदमाशों ने 34 सवारियों से भरी निजी बस को हाइजैक कर लिया था। हाइजैक बस की 34 सवारियां दूसरी बस से झांसी पहुंच गई है। राहत की बात ये है कि बस में बैठी सभी 34 सवारियां सुरक्षित हैं। लेकिन हाईजैक बस का अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। बस अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है। सीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मामले में डीएम आगरा व एसएसपी को कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अवस्थी ने कहा कि डीएम और एसएसपी से मामले में रिपोर्ट भी तलब की गई है। उन्होंने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं।

अवैध गैस रीफिलिंग में पुलिस ने कसा शिकंजा

एजेंसी मालिक समेत 16 गिरफ्तार

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ के विभूतिखंड पुलिस ने बुधवार को एक गैस एजेंसी पर छापा मारकर अवैध गैस रीफिलिंग करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गोरखधंधे में लिप्त पकड़े गए लोगों में गैस एजेंसी मैनेजर और मालिक सहित 16 लोग पकड़े गए है। इसमें कुछ डिलावरी मैन को भी इस कारोबार से जुड़े होने की बात सामने आई है। इनके पास से गैस रिफिलिंग की मशीन और भारी मात्रा में अवैध छोटे-बड़े और कामर्शियल सिलिंडर बरामद हुए है। उधर, विभूतिखंड थाने पर हिरासत में लिए गए लोगों के परिजन व ऑल इंडिया एलपीजी वितरक संघ के पदाधिकारियों की भीड़ इक्टठा हो गई। पुलिस पर परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि तीन दिन से गैस एजेंसी के कर्मचारियों व डिलीवरी बॉय को थाने पर बैठाया गया। पुलिस ने कोरोना संक्रमण के बावजूद एक ही कमरे में 35 आरोपी बैठाया हुआ है। पुलिस को मामले में गहनता से जांच करने के बाद ही कर्मचारियों को गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात देवा रोड पर स्थित एक गैस एजेंसी में भारी मात्रा में अवैध गैस रीफिलिंग की जानकारी मिली। जिसके बाद विभूतिखण्ड पुलिस ने छापा मारकर गैस रिफिलिंग के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर एजेंसी मालिक समेत 16 लोगों को दबोच लिया। बता दे, शहर में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ जेसीपी नवीन अरोरा के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें दुकानों और गैस एजेंसी की आड़ में गैस रिफिलिंग करने वालों की धरपकड़ की जा रही है। पुलिस टीम ने अभी तक करीब दो दर्जन लोगों से पूछताछ की है। जिसमें कई गैस एजेंसी के मालिकों के नाम सामने आए हैं। इसमें गैस दुकानदार से लेकर गैस एजेंसी से जुड़े लोग भी हैं। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि पूरे लखनऊ में गैस रीफिलिंग करने वाले गिरोह का जाल फैला हुआ है। पूरे मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपितों को खिलाफसख्त कार्रवाई की जाएगी।

लीगल ब्लड फाउंडेशन ने काकोरी में जगायी शिक्षा की अलख

कोरोना संकट काल में संस्था की ओर से किया गया ग्रामीणों को जागरुक

लखनऊ, संवाददाता। लीगल ब्लड फाउंडेशन संस्था ने कोरोना संकट काल में शिक्षा से ग्रामीण बच्चों को जोड़ने के लिए व्यापक जनजागृति अभियान शुरू किया है। इस क्रम में संस्था की ओर से काकोरी के बच्चों को न केवल मास्क और सैनिटाइजर देकर जागरुक किया गया बल्कि उन्हें बाकायदा शिक्षित करने की सेवा भी शुरू की गई। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अभिज्ञान प्रकाश ने अपने सहयोगी संचित अग्रवाल, पुष्पेंद्र राय और अनमोल के साथ मिल कर काकोरी ब्लाक के तेज किशन खेड़ा और पुरैना गांव में 400 से अधिक बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर, बिस्किट और पानी की बोतले वितरित कर कोरोना बीमारी से बचाव के लिए जागरुक किया। उन्होंने बताया कि चूंकि मार्च से विद्यालय बंद चल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण बच्चे जो आधुनिक ऑनलाइन क्लासेज नहीं कर सकते उन्हें शिक्षा के महा अभियान से जोड़ने के लिए उन्होंने बाकायदा वहां जाकर कक्षाएं शुरू की। वहां ब्लैक बोर्ड मार्कर पेन की सहायता से अंग्रेजी वर्णमाला और गणित में पहाड़ा का पाठ पढ़ाया गया। इस अवसर पर उपस्थित काकोरी ब्लाक के ब्लाक प्रमुख रामविलास रावत ने कहा कि शिक्षा वरदान है। शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का विकास संभव है।

राज ठाकरे की भाषा बोल रहे शिवराज सिंह चौहान

लखनऊ, संवाददाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर कि "मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के नौजवानों को ही नौकरियॉ मिलेंगी, इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा है कि होने वाले लगभग दो दर्जन से अधिक उप चुनाव में पराजय से बचने के लिये उनका यह हताशा और निराशा में दिया गया असवैधानिक बयान है। भारत का संविधान काश्मीर से कन्या कुमारी तक भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से विचरण करने का, शिक्षा प्राप्त करने का और नौकरी करने का अधिकार देता है, बषर्ते वह अर्हता पूरी करता हो। संविधान की सौगंध लेकर, विधायकों की खरीद फरोख्त करके और तोड़ फोड़ करके मुख्यमन्त्री बनने वाले शिवराज सिंह चौहान जी का यह बयान "व्यापमं" की याद दिलाता है, जिस व्यापमं घोटाले के कारण 52 से अधिक लोगों ने आत्म हत्या कर ली थी, और जो इन्हीं शिवराज सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था। आज वही मुख्यमन्त्री यह बोलें तो ऐसा लगता है कि वह राज ठाकरे की भाषा बोल रहे हैं भा.ज.पा. का शीर्ष नेतृत्व और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी यह स्पष्ट करें कि मध्य प्रदेश में "भारत का संविधान" चलेगा या शिवराज सिंह चौहान का ? मध्य प्रदेश - भारत देश का हिस्सा है या नहीं ? हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर स्थिति स्पष्ट करें। श्री तिवारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गॉधी के उस बयान को सही बताया है कि आज उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद की भयंकर कालाबाजारी हो रही है, जबकि इस समय खरीफकी फसल के लिये यूरिया खाद की सर्वाधिक आवश्यकता है, साधन सहकारी समितियों में किसानों की लम्बी- लम्बी लाइनें है किन्तु "यूरिया खाद" नदारत है, वहीं बाजार में बढ़ी हुई कीमत पर यूरिया खाद खुलेआम बेंची जा रही है। श्री तिवारी ने माननीय मुख्यमन्त्री से अपील की है कि साधन सहकारी समितियों में और सरकारी बिक्री केन्द्रों पर खरीफकी फसल के लिये किसानों को पर्याप्त मात्रा में उचित दाम पर यूरिया खाद उपलब्ध करायें । श्री तिवारी ने कहा है कि अब तो ऑकड़े भी आ गये है और स्पष्ट हो गया है।

एसपी के मंत्री के पाँव सार्वजनिक छूने पर शिकायत

लखनऊ, संवाददाता। दो दिन पूर्व माँ कालिका धाम, अमेठी में प्रदेश के मंत्री मोती सिंह द्वारा दर्शन के लिए जाते समय एसपी अमेठी दिनेश सिंह द्वारा उनके सार्वजनिक रूप से पाँव छूने पर आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने कड़ी आपत्ति की है। डीजीपी यूपी एच सी अवस्थी को प्रेषित अपने पत्र तथा ट्वीट में अमिताभ ने कहा कि एसपी अमेठी दिनेश सिंह ने जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से प्रदेश के एक मंत्री के पाँव छुए, वह पुलिस कप्तान की मर्यादा के प्रतिकूल तो है ही, वह निश्चित रूप से आईपीएस सेवा नियमावली के भी विपरीत है। अतः उन्होंने डीजीपी, यूपी से इसे संज्ञान में लेते हुए यथोचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

गरीबों को प्राविधिक शिक्षा से वंचित करने का प्रयास है 40 आईटीआई का निजीकरण

लखनऊ, संवाददाता। गरीबों को प्राविधिक शिक्षा से बाहर कर उन्हें आज का एकलव्य बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार कर दिया है। विश्वगुरु बनाने के नारे और उसको लागू करने के खोखलेपन ने उत्तर प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। मामला 40 आईटीआई के निजीकरण का है। प्रदेश में पहले ही प्रायवेट के मुकाबले सरकारी आईटीआई की संख्या नगण्य है। 2931 निजी तो 307 पुरुष सरकारी और 12 महिला आईटीआई प्रदेश भर में संचालित हैं। अब इनमें से 40 का निजीकरण किया जा रहा है। पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में 24 के निजीकरण का खाका तैयार किया जा चुका है। निजीकरण के लिये गुणवत्ता सुधारने का तर्क दिया जा रहा है। ये कितना भौंथरा है इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है की प्रदेश के तमाम प्रायवेट आईटीआई में उपयुक्त इमारत नहीं है। प्रयोगशाला और महंगे उपकरणों की बात तो जाने ही दीजिये। शिक्षकों के नाम पर वहाँ एक सूची मात्र है और वेतन कागजों पर वितरित कर दिया जाता है। हां, उपयुक्त राशि दे कर छात्रों को पास कराने की गारंटी वहां रहती है। नए सत्र में प्रवेश इन्हीं निजीक्रत आईटीआई में होगा जिसकी फीस 54 गुना तक ज्यादा होगी। अभी रुपए 480 सालाना से बढ़ कर फीस 26 हजार तक हो जायेगी। जो गरीब छात्र अभी 480 रुपये भरने में असमर्थ हैं, वे 26 हजार रुपये कहाँ से लायेंगे पता नहीं। उधर प्रायवेट लाबी को अरबों रुपए कीमत का बना बनाया स्ट्रक्चर कौड़ी कीमत पर हासिल हो जायेगा। इसमें भ्रष्टाचार की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। मायावती के शासन में चीनी मिलों की बिक्री में धांधली का मामला सबके सामने है। इन आईटीआई में कार्यरत स्टाफ के बारे में भी अभी नीति स्पष्ट नहीं की गई है। उनको अब तक मिल रहे उच्चीक्रत वेतन को कोई निजी आईटीआई दे पाएगी, यह असंभव जान पड़ता है। क्या आत्मनिर्भरता का मोदी-मंत्र गरीबों के लिये उलटा पड़ने वाला है? कोरोना काल में गरीबों के सहारा बने संस्थानों को बेच कर आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। आईटीआई के निजीकरण के फैसले से तो यही साबित होता है। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि गरीबों को प्राविधिक शिक्षा के हक से वंचित करने के इस फैसले को पलट दें। हम गरीबों के हक में आवाज उठाने का संकल्प लेते हैं, और आप से भी अपील करते हैं कि अपनी आवाज उठायें और गरीबों का सहारा बनें। जो भी इस मुहिम का भाग बनना चाहते हैं, कम से कम एक चिट्ठी प्रदेश के मुखिया को तत्काल प्रेषित करें। अपनी क्रिया को मीडिया और सोशल मीडिया तक जरूर पहुंचायें। इंसान के जीवन की सार्थकता जरूरतमंदों के हक में आवाज उठाने में है, किसी ढिंढोरची के कहने पर थाली- ताली बजाने में नहीं।

तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर विक्की सवार महिला की दर्दनाक मौत, पति घायल

- पुलिस ने नाराज ग्रामीणों द्वारा 15 मिनट तक किए गए जाम को समझा-बुझाकर खुलवाया
- चालक समेत ट्रक पुलिस के कब्जे में, शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

बिन्दकी, फतेहपुर । तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से अपने पति के साथ विक्की में पीछे बैठी महिला की कुचल कर मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उसका पति घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर भीड़ लगी रही। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। उधर ग्रामीण शव को लेकर घटनास्थल से 03 किलोमीटर दूर बांदा सागर मार्ग में ले जाकर जाम लगा दिया। गनीमत यह रही कि मात्र 15 मिनट तक ही जाम लगा। पुलिस और सपा पूर्व जिला अध्यक्ष ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम को खुलवा दिया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के अनुसार नगर के ललौली रोड पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार ट्रक से कुचलकर अपने पति के साथ विक्की में सवार गुंजा देवी सविता उम्र 35 वर्ष पत्नी राजकुमार सविता उर्फ लल्ला सविता निवासी चकहाता कोतवाली बिंदकी की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उसका पति राजकुमार सविता उर्फ लल्ला सविता घायल हो गया। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर फेरन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सिंह पर पहुंचे पुलिस शव को कब्जे में लेकर जा रही थी, तभी कुछ ग्रामीणों को लेकर घटनास्थल से 03 किलोमीटर दूर भवानीपुर गांव ले गए जहां पर बांदा सागर मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की जानकारी होने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामेश्वर दयाल दयालु भी पहुंचे। पुलिस और सपा नेता ने नाराज ग्रामीणों को समझाया और 15 मिनट में ही जाम खुल गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल राजकुमार सविता उर्फ लल्ला सविता को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया पुलिस ने चालक समेत ट्रक को पकड़ लिया है। दुर्घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी का माहौल था ग्रामीणों का आरोप था कि तेज रफ्तार ट्रकों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है। खासकर बाईपास अधूरा होने के कारण भारी वाहन नगर के अंदर से गुजरते हैं। इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं और लोग मौत का शिकार होते हैं।

पुलिस आपकी सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगी

प्रयागराज। पुलिस आपकी सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगी।प्रयागराज में पुलिस आम जन को सुरक्षा देने के साथ ही खून भी दे रही है। पुलिस ने एक वेब साइट लांच की है। इस वेबसाइट के द्वारा पुलिस मित्र परिवार से आम जनता ब्लड ले सकती है। ब्लड के जरूरतमंद इस पुलिस मित्र साइड पर जा कर अपने ब्लड ग्रुप को और जरूरत को बता कर ब्लड प्राप्त कर सकते हैं।पुलिस इस कदम के द्वारा समाज की भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास कर रही है।पुलिस मित्र की वेबसाइट का उद्घाटन प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक कविन्द्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। इस मुहिम में 12 स्टेट में ये ग्रुप काम कर रहा है 10 हजार से ज्यादा लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं।1500 से ज्यादा यूनिट ब्लड ये ग्रुप दे चुका है।

दीवार ढही, वृद्ध घायल

फतेहपुर । असोथर थाना क्षेत्र के ग्राम सातोंपीर में बुधवार की सुबह दीवार ढह जाने से उसके नीचे दबकर 55 वर्षीय वृद्ध बुरी तरह घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सातोपीर निवासी स्व. बैजनाथ का पुत्र झल्लू प्रसाद आज सुबह लगभग नौ बजे अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी अचानक पक्की दीवार भरभराकर गिर गयी। जिसके मलबे के नीचे झल्लू दब गया। उधर परिवार के अन्य सदस्य व गांव वालों ने जल्दी-जल्दी मलबा हटाया और आनन-फानन वृद्ध को सरकारी एम्बुलेन्स द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया।

लापता विवाहिता की रिपोर्ट दर्ज

जहानाबाद, फतेहपुर । थाना क्षेत्र के नसेनिया गांव की एक विवाहिता युवती गांव से लापता हो गई है। खोजबीन के बाद पति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नसेनिया गांव के वीरेंद्र कुमार उत्तम की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार उसकी 30 वर्षीय पत्नी पिंकी 31 जुलाई को गांव से अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। अनहोनी की आशंका पर उसने जहानाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि महिला की खोजबीन की जा रही है।

डेढ़ दर्जन पर शांतिभंग की कार्यवाही

फतेहपुर । जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत बुधवार की सुबह पुलिस ने क्षेत्र में आतंक व अशांति फैलाने वाले एक दर्जन से अधिक लोगों के विरूद्ध 151 के तहत कार्यवाही की है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार हुसैनगंज थानाध्यक्ष छः, बिन्दकी दो, कल्याणपुर दो, जाफरगंज दो, गाजीपुर दो, ललौली दो तथा हुसैनगंज थानाध्यक्ष ने दो लोगों के खिलाफशांतिभंग की कार्यवाही की है।

तमंचा के साथ युवक गिरफ्तार

खागा, फतेहपुर । पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के दिशा निर्देशन में चलाये गये धर पकड अभियान के तहत किशनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध असलहा के साथ युवक को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार किशनपुर थानाध्यक्ष अपने हमराह सिपाहियों के साथ क्षेत्र में कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के उद्देश्य से गश्त कर रहे थे। तभी मुखबिर की सटीक सूचना पर किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से खडे राजा उर्फछोटू पुत्र लिपटे निवासी पिपरहा को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से एक बारह बोर का तमंचा व दो जिन्दा कारतूस बरामद कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की है।

नशेबाज पुत्र ने पिता को पीटा

चौडगरा, फतेहपुर । औग थाना क्षेत्र के बड़ाहर गांव में नशेबाज बेटा सूरज पुत्र हरिप्रसाद जो अपने पिता हरिप्रसाद को नशे के हालात में आकर घरेलू विवादों को लेकर जमकर पीट दिया। वही भुक्तभोगी पिता ने अपने बड़े बेटे विजयकांत को सूरज द्वारा आए दिन मारने पीटने व विवाद मचाने की सूचना दी। वही कानपुर में रह रहे विजयकांत ने तत्काल डायल हड्डेड 112 पर कॉल की। जिस पर मौके में पहुंची पीआरबी 1165 ने पीड़ित पिता से जानकारी ली। वहीं नशेबाज पुत्र सूरज जो पुलिस के आते ही मौके से फरार हो गया। वही पुलिस काफी देर तक नशेबाज की खोजबीन करती रही, लेकिन मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने पीड़ित पिता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

गंगा में डूबने से युवक की मौत

फतेहपुर । गाजीपुर थाना क्षेत्र के गांव चकअल्ली पुर के निवासी पाल बिरादरी के युवक की असनी गंगा घाट पर उस समय डूबने से मौत हो गयी। जब वह भदई अमावस्या के अवसर पर गंगा स्नान करने गया था। समाचार लिखे जाने तके गोताखोर युवक का शव बरामद नहीं कर पाये थे।

बाइस लोगो की आयी कोरोना संक्रमित रिपोर्ट

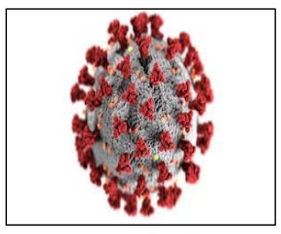

फतेहपुर । कोरोना वायरस संक्रमितो की ताजा रिपोर्ट में पिछले 24 घण्टे के दौरान जनपद में 22 और संक्रमितो की पुष्टि हुई है। जनपद में कोरोना के ऐक्टिव केस बढ़कर 214 हो गये हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 663 है। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 954 हो चुकी है।

सैंकापुर में ट्रांसफार्मर बदले जाने पर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग का अदा किया शुक्रिया

जहानाबाद, फतेहपुर। विकासखंड देवमई क्षेत्र के मिर्जापुर मकरंदपुर के मजरे सैंकापुर (सरायं बदले) में विगत 02 सप्ताह से फुंके ट्रांसफार्मर बदले जाने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग समेत समाजसेवी/ग्राम प्रधान शानदार नकवी, राम बहादुर निषाद के प्रति आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि बीते दो सप्ताह से मिर्जापुर मंकरदपुर के मजरे सैंकापुर (सरायं बदले) के निवासी पुराने युग ढिबरी तथा मोमबत्ती पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। गांव के ही राम बहादुर निषाद ने अपने गांव की समस्या देख उच्चाधिकारियों से अवगत कराया। विभागीय अधिकारियों से लगातार पहल कर आज जैसे ही 02 सप्ताह बाद ट्रांसफार्मर आया तो ग्रामीणों में खुशी का ठिकाना देखते ही बन रहा था तथा लोग विद्युत विभाग सहित

स्थानीय पत्रकार को धन्यवाद देते नजर आ रहे थे। विद्युत उपखंड जहानाबाद से जेई सुरेश कुमार ने बताया कि लोड अधिक होने से ट्रांसफार्मर फुंक गया था जिसे बदल दिया गया है। विद्युत कर्मचारियों को भेजकर रखा गया है और विद्युत आपूर्ति कुछ घंटों बाद जारी कर दी जाएगी। इस मौके पर युवा समाज सेवक शोएब उर्फ गोलू मिर्जापुर, गुलफाम कुरैशी, दिनेश कुमार, रामशंकर, शिवराम निषाद, शिव शंकर निषाद आदि ग्रामीणों ने उक्त लोगो को आभार व्यक्त किया।

नेहरू युवा संगठन टीसी ने 35 जरूरतमंद परिवारों को दी मदद

फतेहपुर । एसोसिएशन फॉर एडोकेसी एन्ड लीगल इनेसिटिव, (आली) लखनऊ के सहयोग से नेहरू युवा संगठन टीसी द्वारा कोरोना महामारी काल में बेरोजगारी व खाद्यन्न अभाव से जूझ रहीं बेसहारा, वृद्ध महिलाओं की सहायतार्थ 35 जरूरतमंदों को ग्राम ऐलई, खागा में वितरित किया गया। संगठन ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लगाए गए लॉकडाउन से उत्पन्न बेरोजगारी व भुखमरी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से संस्था राहत कार्यक्रम के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेसहारा, एकल, वृद्ध महिलाओ को राहत पहुचने हेतु अभियान संचालित किया है। राहत कार्यक्रम के तहत विकास खंड ऐरायां के ऐलई में पूर्व में चिह्नित महिलाओं को 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 2 किलो चीनी, चायपत्ती, मसाला, साबुन आदि वितरित किया गया। कोरोना महामारी से जन समुदाय के मध्य उपजी विभिन्न तरह की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न की है क्योंकि रोजाना कमाने खाने वाले वंचित समुदाय की रोजगार रूक गया है। ऐसी स्थिति में समाज सेवी संगठनों की जिम्मेदारी वंचित समुदाय को राहत पहुचाने के प्रति बढ़ जाती है। संगठन विगत चार माह से कोरोना संक्रमण काल में लगभग एक हजार जरूरतमंद समुदाय को राहत सामग्री का लाभ दे चुका है। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद साहू, रमेशचंद्र, आली संस्था की परामर्श दात्री अनीता वर्मा, कामता सिंह, मयंक साहू, सलमा खातून, इरफान आदि ने सराहनीय योगदान दिया।

पूरा हुआ एक हजार पौधों के रोपण का संकल्प

फतेहपुर । जनपद के 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को पर्यावरणीय दृष्टि से समृद्ध करने हेतु नेहरू युवा संगठन टीसी द्वारा बजाज इलेक्ट्रिक लिमिटेड व फतेहपुर फोरम के सहयोग से मलवां, तेलियानी, बहुआ, भिटौरा, हसवा, हथगाम, ऐरायां, असोथर, विजयीपुर में दीर्घायु वाले पौध पीपल 200, पखार 200, कैथा 200, नीम 200 व सहिजन के 200 पौधों का रोपण किया गया।

दीवार ढहने से वृद्ध की मौत नाती-नातिन घायल

फतेहपुर । कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गढीवा रेवाडी बुजुर्ग में मंगलवार की दोपहर दीवार ढह जाने से 60 वर्षीय वृद्ध समेत नाती व नातिन दबकर घायल हो गये। जिन्हे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान बुधवार की सुबह वृद्ध की मौत हो गयी। जानकारी के अनुसार खागा कोतवाली क्षेत्र के खुशियारीपुर गांव निवासी स्व. महिपाल का 60 वर्षीय पुत्र विजय बहादुर रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी स्व. भांजी मीरा पत्नी चन्द्रभान के यहां आया था और तब से यहीं था। बताते हैं कि कल दोपहर विजय बहादुर अपनी नातिन लक्ष्मी पुत्री चन्द्रभान, आयुष पुत्र शिवभान के साथ घर के बाहर बैठा था। तभी अचानक पक्की दीवार उन पर जा गिरी। जिसके मलबे के नीचे तीनों गिर गये। शोर शराबा सुनकर परिजन व गांव वालों ने तत्काल मलबा हटाया और घायलों को बाहर निकाल आनन-फानन सरकारी एम्बुलेन्स द्वारा उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया।

समाजवादी विचारधारा का किया गुणगान

खागा, फतेहपुर । विधानसभा जोन प्रभारी अखण्ड प्रताप सिंह व विधानसभा प्रभारी/समाजवादी महिला सभा जिलाध्यक्ष संगीता राज पासी ने विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर व बूथों में जाकर कमेटियों का गठन किया व पूर्व की अखिलेश सरकार की उपलब्धियों का बखान कर जन-जन को पार्टी का सदस्य बनाने की अपील की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष मतीन अहमद, विजय, फुज्जा भाई, बिन्नू यादव आदि मौजूद रहे।

भदई अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने की गंगा आरती

फतेहपुर । गंगा बचाओ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र शरन सिम्पल द्वारा अमावस्या पर ओमघाट मे गंगा आरती का आयोजन किया गया जिसमे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए गंगा आरती की गयी आरती। गंगा बचाओ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र शरन सिम्पल द्वारा आयोजित गंगा आरती में शामिल होने पहुंचे भक्तगणों ने पहले घाट की साफसफाई कर स्वच्छता का दिया संदेश। समिति के प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र शरन सिम्पल ने स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते हुये कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि गंगा में किसी प्रकार की सामाग्री को न डाले। इस मौके स्वामी विज्ञानानंद महाराज, समिति के विनोद गुप्ता, अरुण जायसवाल एडवोकेट, सुरेन्द्र पाठक, आचार्य सूर्यभान सिंह, योगेश कुमार, श्रीकृष्ण चन्द्र, दुर्गेश कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।

व्यापार मण्डल का सदस्यता अभियान जारी

एक हजार लोगो को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित

खागा, फतेहपुर । उद्योग व्यापार मण्डल प्रदेश अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा के निर्देशन पर चलाये जा रहे सदस्यता अभियान के क्रम में 19 अगस्त को सम्बद्ध इकाई खागा में सदस्यता अभियान चलाकर प्रथम चरण में 121 व्यापारियों को संगठन का सदस्य बनाया। अध्यक्ष अरुण केसरवानी के नेतृत्व में चलाये जा रहे सदस्यता अभियान का लक्ष्य एक हजार व्यापारियों को संगठन से जोड़ने का तय किया गया है। व्यापारियों की रक्षा, सुरक्षा, हितो व सम्मान की रक्षा का उद्देश्य में वचनबद्ध खागा व्यापार मण्डल राष्ट्रहित, समाजहित, जनहित, व्यापारहित के कार्यो में बढ़-चढ़ कर अग्रणी भूमिका का निर्वाहन करेगा। महामंत्री महेन्द्र गुप्ता ने कहा शीघ्र ही खागा के आस-पास समस्त ग्रामो में संगठन की इकाई का गठन किया

जाएगा। युवाध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा बड़ी संख्या में युवा व्यापारियों को संगठन से जोड़कर संगठन की मजबूत श्रृंखला तैयार की जायेगी। कोषाध्यक्ष मनीष केसरवानी ने कहा खागा व्यापार मण्डल मुख्यालय में बन रहे व्यापार भवन में अपनी पूर्ण हिस्सेदारी प्रदान करेगा। छः चरणों मे चलने वाले सदस्यता अभियान के प्रथम चरण में संजय गुप्ता राजेन्द्र पांडेय, सुरेश सिंह इम्तियाज अहमद ने सहभगिता की, द्वितीय चरण का सदस्यता अभियान 26 अगस्त से प्रारम्भ होगा। व्यापार मंडल खागा के अध्यक्ष शिवचन्द्र शुक्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमिताभ शुक्ल, उपाध्यक्ष रशीद अहमद, संरक्षक डॉ0 शमीम अहमद, मन्त्री मनोज शुक्ल, युवाध्यक्ष विजय अग्रहरी, युवा मन्त्री नदीम सिद्दीकी, सानू वारसी, मो0 कलीम, ननकू राइन, मुन्ना फारूकी, समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

पुलिस उपाधीक्षक नगर को दी गयी भावभीनीं विदाई

नई तैनाती गोरखपुर के लिए हुए रवाना

फतेहपुर । पुलिस लाइन सम्मेलन कक्ष में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर कपिल देव मिश्र का विदाई कर गोरखपुर को रवाना किया गया। सभी उपस्थित अधिकारीगणों द्वारा माल्यार्पण कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी। उनके सराहनीय कार्यो को याद करते हुए विदाई दी गयी। मौके पर क्षेत्रधिकारी लाइन व प्रतिसार निरीक्षक व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। सीओ सिटी कपिल मिश्रा ने कहा फतेहपुर में बिताया हुआ एक-एक पल उन्हें हमेशा याद रहेगा उन्होंने कहा यहां के लोग उन्हें सम्मान देने का काम किया है इसी के चलते वह अपने कार्यो में सफल हो पाए हैं। उन्होंने कहा भले ही आज किसी अन्य जनपद में सेवा देने के लिए जा रहे हो लेकिन फतेहपुर जनपद को कभी भुला नहीं पाएंगे।

गणेश पूजा व मोहर्रम पर्व को लेकर बनी सहमति

खागा, फतेहपुर । आगामी पर्वो गणेश पूजा व मोहर्रम को लेकर कोतवाली परिसर में नागरिकों के साथ प्रशासन ने बैठक की। प्रभारी निरीक्षक आर0के0 सिंह ने बैठक में उपस्थित लोगों को जानकारी दी गयी। कोरोना वायरस के कारण शासन के निर्देशानुसार आने वाले पर्वो गणेश पूजा में किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी बड़ी मूर्ति सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगी। घर पर मूर्ति स्थापित करके पूजा-अर्चना करें, मोहर्रम पर्व में भी ताजिया नहीं रखी जाएंगी और ना ही मोहर्रम पर्व के कोई भी जुलूस नहीं निकाले जाएंगें।

घर पर ही मातम व इबादत करें। बैठक में प्रमुख रूप से

गणेश चतुर्थी व मोहर्रम को लेकर पीस कमेटी की हुई बैठक

कोरोना संक्रमण के चलते गणेश चतुर्थी व मोहर्रम पर्व पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध

धाता, फतेहपुर । कोरोना संक्रमण के चलते इस बार गणेश चतुर्थी व मोहर्रम के पर्व पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। थाना परिसर पर आयोजित पीस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर धर्म संप्रदाय के खिलाफ या गलत अफवाह उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है जिसके संक्रमण के चलते सरकार द्वारा मोहर्रम व गणेश चतुर्थी पर्व को मनाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपनों घरों पर नई मूर्तियों को न लाये और न ही उनका विसर्जन करें। थाना प्रभारी ने कहा की प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। बैठक में प्रमुख रूप से अनुपंम सिंह, अनंत सिंह, सुनील सिंह, सोनू अहमद, फुजैल अहमद, बीरेंद्र केशरवानी, रोहित जोशी, मुशीर अहमद, मोहर्रम अली, ननका केशरवानी, राजा केशरवानी इत्यादि उपस्थित रहे।

मार्ग दुर्घटनाओं में भट्ठा मालिक सहित चार की मौत

फतेहपुर । जनपद के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत बीते चौबीस घण्टों के अन्तराल में हुए सड़क हादसें में भट्ठा मालिक समेत तीन महिलाओं की मौत हो गयी।

जानकारी के अनुसार मलवां कस्बा निवासी स्व. रामबहादुर सिंह का 40 वर्षीय पुत्र सरदार सिंह जो कस्बे में ही स्थित ईट भट्ठा मालिक था। बताते हैं कि आज शाम लगभग साढ़े तीन बजे वह पैदल बाजार जा रहा था। जैसे ही वह सडक पार करने लगा। तभी फतेहपुर से कानपुर की ओर जा रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दिया। जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी लवली सिंह, 13 वर्षीय पुत्री मुस्कान, 8 वर्षीय पुत्री आंचल, 11 वर्षीय पुत्र अभिषेक व 6 वर्षीय कृष्णा को छोड गया है। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम लच्छीखेडा गांव निवासी छेदीलाल की 60 वर्षीय पत्नी श्यामा देवी मंगलवार की शाम अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से किसी काम से जा रही थी। जैसे ही वह गांव से कुछ दूर पहुंची। तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। जिससे महिला की मौत हो गयी।

इसी प्रकार बिन्दकी कोतवाली क्षेत्र के लाल का पुरवा गांव निवासी राजकिशोर की 32 वर्षीय पत्नी गुडिया देवी आज सुबह किसी काम से जा रही थी। जब वह सडक पार करने लगी। तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दिया। जिसके फलस्वरूप उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। इसी क्रम में खागा कोतवाली क्षेत्र के कल्लनपुर गांव निवासी शिवनाथ की 40 वर्षीय पत्नी सीमा देवी मंगलवार की शाम पति के साथ अपनी तीन वर्षीय पुत्री कोमल का इलाज कराने के लिए असोथर थाना क्षेत्र के सातोपीत गांव गयी थी। बताते हैं कि लौटते समय जैसे ही बाइक महिचा मंदिर के समीप पहुंची। तभी अचानक चलती बाइक से गिर जाने से गम्भीर रूप से घायल हो गयी। उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना पर पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर विच्छेदन गृह भेज दिया है।

प्रवासी श्रमिकों को वापस भेजिए

वर्तमान में श्रमिकों का पलायन एक देश से दूसरे देश को और एक राज्य से दूसरे राज्य को भारी संख्या में हो रहा है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को श्रम का पलायन दो कारणों से होता है। पहला कारण भौगोलिक है। जैसे बिहार में कृषि बहुत आराम से हो जाती थी इसलिए वहां के लोगों ने औद्योगीकरण के लिए विशेष प्रयास नहीं किया। दूसरी तरफ पंजाब में भाखड़ा बांध के कारण सिंचाई का विस्तार हुआ और वहां श्रम की मांग बढ़ी। इस प्रकार बिहार के आरामदेह भूगोल और भाखड़ा के सिंचाई के भूगोल के कारण बिहार से पंजाब को श्रम का पलायन हुआ। पलायन का दूसरा कारण शासन की गुणवत्ता है। आज उत्तर प्रदेश के श्रमिक सूरत को पलायन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के उद्यमी भी सूरत को पलायन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश का उद्यमी उत्तर प्रदेश के श्रमिक को सूरत में रोजगार दे रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश का उद्यमी उत्तर प्रदेश में उसी श्रमिक को रोजगार देने को स्वीकार नहीं करता है। आज के युग में माल की ढुलाई आसान है इसलिए कपड़े जैसे उद्योग को उतनी ही आसानी से सूरत में चलाया जा सकता है जितना कि उत्तर प्रदेश में। किसी समय उत्तर प्रदेश में टांडा और बनारस में विशाल कपड़ा उद्योग था। लेकिन उत्तर प्रदेश के ये कपड़ा उद्यमी आज टांडा में उद्योग चलाने के स्थान पर सूरत को स्वयं पलायन कर रहे हैं। कारण यह कि गुजरात की तुलना में उत्तर प्रदेश में शासन की गुणवत्ता न्यून है। यहां पर अधिकारियों का रुख उद्यमी से अधिकाधिक वसूलने का होता है। नेताओं और दबंगों द्वारा वसूली की जाती है। यहां उद्योग को आगे बढ़ाने में व्यवधान आते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश का उद्यमी उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहा है।

कोविड ने बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के तमाम श्रमिकों को मेजबान राज्यों से अपने मूल राज्य को वापस आने के लिए मजबूर कर दिया है। इनके लिए हमारे सामने दो विकल्प हैं। एक यह कि हम इन श्रमिकों को पुनरू उन मेजबान राज्यों में भेजने की व्यवस्था करें जहां ये पहले कार्यरत थे। दूसरा यह कि हम इनके लिए मनरेगा, खाद्य सब्सिडी, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करें जिससे ये अपने मूल राज्य में ही अपना जीवनयापन कर सकें। मूल राज्य में इनको समाहित करने से तीन समस्या पैदा होती है। पहली समस्या यह कि ये प्रवासी श्रमिक सूरत में कपड़ा बुनाई के लूम को चलाने एवं मरम्मत इत्यादि को करने अथवा हीरों को तराशने की दक्षता हासिल कर चुके हैं। वे वहां 1000-1500 रुपये तक दैनिक वेतन पाते थे। और इससे भी ज्यादा वे देश की आय में जोड़ते थे मान लें 2500 रुपए। जब हम इन्हें वापस अपने गांव ले आते हैं तो यहां पर मनरेगा के अंतर्गत इन्हें मिट्टी उठाने का कार्य करना होगा जिस कार्य का देश की आय में योगदान कुल 300 रुपया प्रतिदिन और इन्हें वेतन मात्र 200 रुपये प्रति दिन मिलेगा। इसलिए इनको घरेलू राज्य में समाहित करने से देश के आर्थिक विकास का ह्रास होगा। जो व्यक्ति देश की आय में एक दिन में 2500 रुपये जोड़ सकता था वह अब केवल 300 रुपये ही जोड़ेगा। अपने मूल राज्य में श्रमिक को समाहित करने में दूसरी समस्या यह है कि कृषि में श्रम को समाहित करने की सीमा है। आज विकसित देशों में कुल जनसंख्या का 1 फीसदी से भी कम कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है। अपने देश में स्वतंत्रता के समय लगभग 50 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित थी जो आज घट कर 18 प्रतिशत हो गई है।

आर्थिक विकास के साथ कृषि का महत्व घटता जाता है। ऐसे में इन वापस आये श्रमिकों को कृषि में समाहित करना इन्हें उस क्षेत्र में प्रवेश कराना होगा जहां पहले ही आय न्यून है जैसे इन्हें गड्ढे में धकेला जा रहा हो। इनके प्रवेश करने से कृषि में श्रम की उपलब्धि बढ़ेगी, कृषि श्रमिक के वेतन घटेंगे, इन वापस आये श्रमिकों कि आय और घटेगी। तीसरी समस्या यह है कि मूल राज्यों को इन्हें मनरेगा इत्यादि में रोजगार देने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाने होंगे। ये राज्य जो रकम सड़क अथवा अस्पताल बनाने के लिए उपयोग कर सकते थे उसका उपयोग ये इन श्रमिकों को जीवनयापन करने के लिए देने में करेंगे। चौथा बड़ा नुकसान यह है कि मेजबान देश में श्रमिक की उपलब्धता कम हो जाने के कारण वहां मशीनों का उपयोग बढ़ेगा। जैसे पंजाब में हार्वेस्टर का और सूरत में आटोमेटिक मशीनों का उपयोग बढ़ेगा और इन राज्यों में श्रम की मांग स्थायी रूप से कम हो जाएगी। गुजरात और पंजाब में श्रम की मांग कम होने का अर्थ होगा कि सम्पूर्ण देश में श्रम की मांग कम होगी और श्रम का अस्तित्व कमजोर होगा। इन तमाम कारणों से सरकार को चाहिए कि वापस आये श्रमिकों को शीघ्रातिशीघ्र उनके मेजबान राज्यों में पहुंचाने की जुगत करे। इस दिशा में सरकार को निम्न कदमों पर विचार करना चाहिए। पहला यह कि कानून बनाकर सभी प्रवासी श्रमिकों को आश्वासन देना चाहिए कि यदि कभी दुबारा लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बनी तो उन्हें मेजबान देश में न्यूनतम जीविका उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा कार्य यह कि वापस आये श्रमिकों को मूल राज्य में ही उच्च कोटि के रोजगार उत्पन्न कराने के प्रयास करने होंगे। इसके लिए सुशासन पर ध्यान देना होगा कि उत्तर प्रदेश का उद्यमी उत्तर प्रदेश में ही उद्योग लगाये और यहीं श्रमिकों के लिए रोजगार बनाये। तीसरा यह कि उच्च कीमत के कृषि उत्पाद जैसे गुलाब अथवा ग्लाइडोलस के फूलों के उत्पादन के लिए मिशन बनाना चाहिए।

हर डिवीजन में एक संस्था को मिशन मोड पर कार्य देना चाहिए कि उस क्षेत्र के लिए उपयोगी कीमती कृषि उत्पादों को बढ़ाये जिससे कि कृषि में ही इन लोगों को उच्च वेतन मिल सके। और यह कि मूल राज्यों को नेट आधारित रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रयास करने चाहिए। जैसे हर जिले में विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की संस्था बनाई जा सकती है जिसके आधार पर हमारे युवा एक विदेशी भाषा से दूसरी विदेशी भाषा में अनुवाद करके अपनी जीविका चला सकें। जैसे दरभंगा का युवक जर्मन से जापानी में ट्रांसलेशन कर सके। इन कदमों को उठाने से वापस आये श्रमिकों को अपने मूल राज्य में समाहित करके भी लाभ अर्जित किया जा सकता है।

सम्पादकीय

लघु उद्योगों को प्रश्रय देना जरूरी

अटल बिहारी वाजपेयी जब 1998 में सत्ता आये, उससे ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लघु उद्योगों की परिभाषा में बड़ा परिवर्तन किया था. उससे पूर्व वे उद्योग, जिनमें प्लांट और मशीनरी की लागत 60 लाख रुपये या उससे कम थी, लघु उद्योग कहलाते थे. इस सीमा को अचानक तीन करोड़ कर दिया गया. वाजपेयी सरकार ने लघु उद्योगों की परिभाषा को पुनः बदलते हुए इस सीमा को घटा कर एक करोड़ कर दिया. वर्ष 2006 में एमएसएमइ अधिनियम लागू किया गया. इससे एक नयी परिभाषा एमएसएमइ (माइक्रो, स्माल, मीडियम एंटरप्राइज) लागू हो गयी. इसमें दो प्रमुख बदलाव आये. एक, उद्योग के स्थान पर उद्यम शब्द का प्रयोग शुरू हुआ. दूसरा, एक और वर्ग मध्यम श्रेणी शामिल किया गया. तर्क था कि लघु उद्यमों को मिलनेवाले लाभ, जैसे- सरकारी खरीद में प्राथमिकता, वित्त में रियायत आदि छिन जाने के भय से लघु उद्यमों को विस्तार करने में झिझक होती थी. मध्यम श्रेणी के उद्यमों को भी इसमें शामिल करने पर यह झिझक समाप्त हो जायेगी. नयी परिभाषा के अनुसार, सूक्ष्म उद्यम में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश सीमा 25 लाख, लघु उद्यम में पांच करोड़ और मध्यम श्रेणी में 10 करोड़ रखी गयी. केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद एक नये एमएसएमइ एक्ट हेतु तैयारी शुरू हुई. प्लांट एवं मशीनरी से बदल कर 'टर्न ओवर' के आधार पर श्रेणी बनाने का प्रस्ताव आधिकारिक हलकों से चल रहा था. लेकिन, इसके विरोध के चलते, सरकार ने परिभाषा प्लांट एवं मशीनरी में निवेश और 'टर्न-ओवर' दोनों के आधार पर करना तय किया. 1 जून, 2020 को अध्यादेश जारी कर सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों के लिए निम्न परिभाषा निश्चित की है.

1. सूक्ष्म उद्यम- जिसमें संयंत्र और मशीनरी में एक करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार पांच करोड़ से अधिक नहीं है.
2. लघु उद्यम- जिसमें संयंत्र और मशीनरी में पांच करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा कारोबार 50 करोड़ से अधिक न हो.
3. मध्यम उद्यम- जिसमें संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा कारोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं होता है. इस अधिसूचना को 1 जुलाई, 2020 से लागू कर दिया गया है. चूंकि, ऐसे कई उद्यम हैं, जहां संयंत्र, मशीनरी एवं उपस्कर तो कम होते हैं, लेकिन उनका टर्नओवर काफी ज्यादा है. इस प्रकार भारी कारोबार वाले उद्यम भी एमएसएमई की श्रेणी में आ जाते थे. इसलिए 'निवेश' और 'कारोबार' दोनों के समिश्रण से उस समस्या का समाधान तो हो गया है. लेकिन, अध्यादेश के अन्य प्रावधानों के चलते यह विवादों में है. लघु उद्योगों के कई संगठनों की आपत्ति है कि नयी व्यवस्था में विदेशी पूंजी प्राप्त उद्योगों को अलग नहीं किया गया है. उनका मानना है कि लघु उद्यमों का स्थान वे हस्तगत कर लेंगे. पहले मात्र 0.007 प्रतिशत उद्यम ही मध्यम श्रेणी में थे. अब लघु उद्यम कहलायेंगे, क्योंकि इनमें 10 करोड़ से कम निवेश है. इसलिए, वर्तमान में मध्यम दर्जे के उद्यमों को तो कोई लाभ नहीं मिलेगा. दूसरी आपत्ति है कि पूर्व के एमएसएमइ अधिनियम, 2006 के अनुरूप मैन्युफैक्चरिंग और सेवा उद्यमों में भेद नहीं किया गया है. पहले सूक्ष्म उद्यमों में सेवा क्षेत्र में संलग्न उद्यमों की निवेश की सीमा मात्र 10 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख थी. लघु सेवा उद्यमों में निवेश सीमा दो करोड़ रुपये और मध्यम सेवा उद्यमों में पांच करोड़ रुपये थी. लघु मैन्युफैक्चरिंग उद्यम रोजगार सृजन के अवसरों के नाते जाने जाते हैं. सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावनाएं मैन्युफैक्चरिंग से बहुत कम होती हैं. ऐसे में सेवा क्षेत्र को मैन्युफैक्चरिंग के समकक्ष रखना सही नहीं होगा. इसलिए, ट्रेडिंग और असेंबलिंग आदि सेवाओं को मैन्युफैक्चरिंग से भिन्न माना जाना ही सही होगा. तीसरी अपत्ति है कि लघु उद्यमों में निवेश की सीमा पांच करोड़ से 10 करोड़ रुपये की गयी है, लेकिन मध्यम श्रेणी के लिए यह 10 करोड़ से बढ़ा कर 50 करोड़ यानी पांच गुना कर दी गयी है. वास्तव में यह बड़े उद्यमों को लाभ देनेवाला है, क्योंकि वित्त, सरकारी खरीद आदि में अब उनकी हिस्सेदारी बढ़ जायेगी.

दूसरा, लघु उद्यम संगठनों की मांग है कि एमएसएमइ में विदेशी निवेश प्राप्त उद्यमों को एमएसएमइ परिभाषा शामिल नहीं किया जाना चाहिए. एक अन्य आपत्ति यह है कि जब 'टर्न ओवर' का प्रश्न आता है तो उसमें से निर्यात के कारोबार को हटा कर देखा जायेगा. इस बात का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यदि कोई बड़ा उद्यमी (या निर्यातक) जिसका निवेश कम है, लेकिन बड़ी मात्रा में निर्यात करता है, तो वह देश के एमएसएमइ के समकक्ष आ सकता है. फर्मों को उसके आकार और कुल कारोबार के अनुसार ही वर्गीकृत किया जाना चाहिए. किसी भी हालत में निर्यात अथवा किसी और बहाने से बड़ी फर्मों को एमएसएमइ की श्रेणी में लाया जाना, लघु उद्यमों को प्रश्रय देने के औचित्य को ही समाप्त कर देगा. सरकार को वर्तमान नोटिफिकेशन पर नये सिरे से विचार कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों को परिभाषित करना चाहिए, ताकि रोजगार, वितरण में समानता, विकेंद्रीकरण आदि के लक्ष्यों को भलीभांति प्राप्त किया जा सके.

अगस्त, 1947 से गुजरकर ही गांधी तक पहुंचा जा सकता है

अगस्त का महीना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिये सिर्फ इसलिये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसी माह के दौरान देश ने पहले 1920 में असहयोग आंदोलन और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़े थे। आधुनिक युग में देश की वैचारिक गठन के लिये एक अकेला व्यक्ति जो सबसे अधिक जिम्मेदार हैय और जिसने देश के सर्वाधिक क्षेत्रों व लोगों के साथ विभिन्न विचारधाराओं को प्रभावित किया, यानी कि महात्मा गांधी- वे अगस्त 1947 में ही एक तरह से अपने जीवन रूपी तप की पूर्णाहुति की ओर बढ़ चले थे। गांधीजी ने अपनी सारी वैचारिक दौलत इसी माह में खर्च की थी। उनके सारे मूल्यों और आदर्शों को इसी दौरान कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा था। जिस प्रकार राम के चरित्र की पराकाष्ठा सीता की अग्नि परीक्षा में, कृष्ण की कुरुक्षेत्र, अब्राहम लिंकन की दास प्रथा की समाप्ति हेतु हुए गृह युद्ध, जनरल सैम मानेकशा की 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की 2011 के एक दिवसीय मैच के फाइनल में हुई थी, उसी प्रकार गांधी की मानवीयता और नैतिक शक्ति का चरम हमें इसी दौरान देखने को मिला था। यह वह समय था जब अंग्रेजों ने अपने शासन को समेटना शुरू कर दिया था और भारत की दहलीज पर स्वातंत्र्य देवी पधार चुकी थी। साथ ही मुल्क को बांटती रेखा के कारण हिंदू, मुसलमान और सिख कौमें हिंसा के दावानल में झुलस गई थीं। दुनिया ने एक ही देश से उभरे दूसरे देश के बीच ऐसी वैमनस्यता और सैकड़ों वर्षों से साथ रहते आये सम्प्रदायों में इस तरह की कटुता पहली बार देखी थी। लाखों मारे गये, करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति स्वाहा हो गई और मानव जाति की याददाश्त का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। यह पूरी दुनिया के लिये एक तरह से स्तब्धकारी घटना इसलिये थी क्योंकि देश ने अन्यान्य तरीकों को नकारकर गांधी के बताए रास्ते पर चलकर, अर्थात अहिंसा के जरिये आजादी लेना तय किया था। गांधीजी का मानना था कि हिंसा से प्राप्त स्वाधीनता हिंसक समाज बनायेगी। गांधी विचारधारा के दो प्रमुख तत्वों (सत्य व अहिंसा) में एक का लोप तो उनकी आंखों के सामने तभी से हो रहा था, जब आजादी ने दस्तक दी ही थी। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का जैसा बाजार भाव चढ़ा, गांधी के लिये वह सबसे बड़ा झटका था। हिंदू-सिख एक तरफ और मुसलमान दूसरी ओर तभी हो गये जब पाकिस्तान नामक देश का जन्म भारत की कोख से होना तय हो गया था। देश का माहौल हिंसक हो गया था। सबसे बुरी स्थिति पंजाब और बंगाल-बिहार की थी। रियासत के विलीनीकरण के मसले को लेकर कश्मीर से लौटने के बाद बापू ने बंगाल में खूंटा गाड़ दिया था। आजादी मिलने के एक-दो दिन पहले से ही पूरे देश में आनंद और उत्साह का माहौल था। बंगाल में बैठे गांधीजी ने न कहीं झंडा फहराया, न ही किसी जश्न में भाग लिया। ऊल्टे, उन्होंने उस दिन (15 अगस्त को) उपवास रखा और चरखा काता था। अलबत्ता, उन्होंने इस दिन को लम्बे समय तक उनके सहयोगी व निजी सचिव रहे श्महादेवभाई देसाईश् के नाम पर याद रखने को कहा। यहां तक कि जब प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुके जवाहरलाल नेहरू 14-15 अगस्त की दरमियानी रात को 12 बजे कांस्टिट्यूशन असेंबली हॉल में पढ़े जाने वाले अपने ऐतिहासिक भाषण श्ट्रिस्ट विद डेस्टिनीश् को संध्या समय में अंतिम रूप दे रहे थे, गांधी सोने के लिये जल्दी चले गये थे। एक शाम पूर्व प्रारंभ किया गया उपवास उन्होंने 15 की शाम को तोड़ा, फिर वे बेलियाघाट के रास बिहारी मैदान में टहलने व प्रार्थना करने गये। उनकी जीवनी लिखने वाले डीजी तेंदुलकर के अनुसार, सामान्य दिनों में 5 मिनटों में पूरा चक्कर लगाने वाले बापू को भीड़ के कारण 20 मिनट लग गये। यहां अपने भाषण में उन्होंने खिलाफ़त आंदोलन के संदर्भ के साथ हिंदू-मुसलिम एका पर बल दिया। 16 अगस्त को उन्होंने बंद होने की कगार पर पहुंचे अपने पत्र हरिजन में मिरेकल ऑर एक्सिडेंट (करिश्मा या दुर्घटना) शीर्षक से सम्पादकीय लिखकर साम्प्रदायिक एकता का महत्व व जरूरत बतलाई थी। 17 अगस्त को इसी समाचारपत्र के लिये उनका लिखा सम्पादकीय श्एन इंडियन गवर्नरश् शीर्षक से छपा, जिसमें उन्होंने आजाद भारत में प्रशासन संबंधी अपने विचार रखे। 18 अगस्त को ईद थी। उनसे मिलने बड़ी संख्या में मुस्लिम आये, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री डॉ. पीसी घोष आये, करीब एक लाख लोगों ने उनके दर्शन किये। इन सभी से बातचीत में उन्होंने विभिन्न धर्मावलम्बियों के बीच एकता बढ़ाने और हिंसा के पूर्णतरू त्याग पर दिया था। इसी दिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी प्रो. विलियम स्टुअर्ट नेल्सन से। भारत में रहकर करीब दो दशकों तक अहिंसा पर अध्ययन करने वाले इस अमेरिकी विद्वान ने अविभाजित बंगाल में दंगा-पीड़ितों की मदद हेतु गांधीजी का हाथ बंटाया था और उनके साथ शांति मोर्चों में शामिल हुए थे। बाद में वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हुए, जहां उन्होंने गांधी पर अध्ययन की स्वतंत्र व्यवस्था कराई थी। गांधी के 150वें जयंती वर्ष के अवसर पर अमेरिका के लिंकन विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को उनकी याद में एक सेमीनार भी कराया गया था, जिसका शीर्षक था- ए ब्रदर इन द स्पिरिट ऑफ गांधी। इसमें नेल्सन और गांधीजी के संबंधों की पार्श्वभूमि में भारत के अहिंसक स्वतंत्रता आंदोलन पर चर्चा की गई थी जिसमें अनेक विद्वानों ने हिस्सा लिया था। नेल्सन को एक तरह से डॉ. मार्टिन लूथर किंग का मेंटर माना जाता है, जिनकी सलाह पर ही किंग ने 1959 में भारत की यात्रा की थी और लौटकर माई ट्रिप टू द लैंड ऑफ गांधी और पाम संडे सर्मन ऑन मोहनदास के. गांधी के नाम से लेख लिखे थे। बहरहाल, स्वदेश लौटने के पूर्व वे 1946 में गांधीजी से अंतिम बार मिलने आये थे। तब उन्होंने पूछा था कि जिन भारतीयों ने अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त की है वे उसी की शक्ति द्वारा आखिर गृह युद्ध की सी हिंसा को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्या वे अब तक भय से अहिंसक बने हुए थे? गांधीजी ने यह स्वीकार किया था कि इसका जवाब तलाशा जाना चाहिये। उनके कई ब्रिटिश मित्र भी यह जानना चाहते हैं। गांधी ने इतना ही कहा कि अगर अहिंसा को सविनय अवज्ञा की आड़ में छिपाया गया है तो भारत फिर कभी इस विचार (अहिंसा) को प्राप्त नहीं कर पायेगा। वैसे उन्होंने कहा कि अगर वे स्वयं (गांधी) भी इस कल्पना में जीते रहे हैं तो भी इसका उन्हें पछतावा नहीं है। यह संयोग है या इतिहास का घटनाक्रम, कि अगस्त, 1947 के दौरान गांधीजी द्वारा जो कहा-लिखा अथवा किया गया, वह सारा कुछ गांधी के जीवन भर के अर्जित विचारों, अनुभवों और प्रयोगों के सारतत्व के रूप में सामने आया था। हालांकि गांधी के जीवन में घटनाओं व विषयों की इतनी भरमार है कि उन्हें निष्कर्षों में समेटने की बात तो दूर, समझने में ही एक पूरा जीवन लग सकता है, तो अकेला एक महीना उनके पूरे जीवन-दर्शन व सत्व को कैसे सकेल सकता है? फिर भी, इन कुछ दिनों में ही उनके व्यक्तित्व का सर्वाधिक सामने आता है। उनके सत्य और अहिंसा के दर्शन तो दांव पर ही लग चुके थे। उनके सारे सिद्धांतों के साथ उनकी बौद्धिकता, संवेदना, विवेकशीलता और नेतृत्व क्षमता को सबसे बड़ी चुनौती इसी दौरान मिली और उन सभी से वे सफल होकर गुजरे। उनकी इसी कामयाबी पर सी. राजगोपालाचारी ने कहा था- गांधीजी ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं लेकिन वे वैसी महान नहीं हैं, यहां तक कि स्वाधीनता भी नहीं जो अपने-आप में अद्भुत हैय और वह है बुराई पर उनकी विजय। गांधीजी सेना व पुलिस से विहीन राज्य की कल्पना करते थे। जिन लोगों के लिये यह अवधारणा हास्यास्पद या कपोल- कल्पना है, वे इसे जान लें कि अगर लोगों में नैतिकता और विवेक का उच्चतम स्तर है तो मनुष्य इन बलों के बिना भी रह सकता है। यह कोई कहने की बात नहीं थी बल्कि गांधी ने वह कर दिखलाया था। एक मुस्लिम लीगी समाचारपत्र मॉर्निंग न्यूज ने कोलकाता के मुस्लिमों की ओर से उन्हें सम्मान देते हुए लिखा था-गांधी मरने के लिये तैयार थे, ताकि वे (मुस्लिम) शांति के साथ जीवित रह सकें। द टाईम्स के संवाददाता ने कोलकाता की परिस्थितियों के विवरण का उपसंहार करते हुए लिखा-जो सेना के अनेक जवान मिलकर ही कर सकते थे, वह गांधीजी ने अकेले करके दिखलाया है। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबेटन ने गांधी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पत्र लिखा था-पंजाब में 55 हजार सैनिक थे फिर भी वहां भीषण दंगे हुए। बंगाल में हमारी सेना एक व्यक्ति तक सीमित थी, और वहां कोई दंगा नहीं हुआ। एक प्रशासक के तौर पर मुझे एक व्यक्ति में समाहित इस सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने की अनुमति दें! 7 सितम्बर, 1947 को जब बापू दिल्ली के लिये रवाना हुए थे तब तक वे कोलकाता में पूरे 30 दिन गुजार चुके थे, सर्वाधिक बेलियाघाट में- 24 दिन। जब उनसे जनता के लिये कोई पैगाम देने के लिये कहा गया, तो उन्होंने बंगाली में लिखकर दिया- मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। बेशक, अगस्त, 1947 से गुजरकर ही कोई गांधीजी के भीतर तक उतर सकता है।

कर निर्धारण की नयी प्रणाली

फेसलेस एसेसमेंट भी टैक्स एसेसमेंट की एक सामान्य-सी प्रक्रिया है, जहां ऑनलाइन आपका मूल्यांकन होता है और आपको यह भी पता नहीं चलता कि कौन-सा अधिकारी आपका मूल्यांकन कर रहा है. उस अधिकारी को भी आपके बारे में कुछ पता नहीं होता कि आप कौन हैं? वह केवल वित्तीय लेन-देन का ऑनलाइन मूल्यांकन करता है. फेसलेस एसेसमेंट को अगर साधारण भाषा में समझें, तो यह टेक्नोलॉजी के माध्यम से करदाता द्वारा जमा किये गये कर का मूल्यांकन है. यह प्रक्रिया तो शुरू भी हो चुकी है. फेसलेस होने का सबसे बड़ा लाभ है कि इससे पारदर्शिता आयेगी और भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी. चूंकि इस प्रक्रिया के तहत करदाता और आयकर अधिकारी का एक-दूसरे से आमना-सामना नहीं होगा, ऐसे में तमाम तरह के कदाचार पर लगाम लगेगी. आयकर मूल्यांकन तो कुछ समय से फेसलेस होने लग गया है, लेकिन अपील अब भी फेसलेस नहीं है. इसमें करदाता और अधिकारी का आमना-सामना होता है. एक करदाता को अपील के लिए आयकर अधिकारी के पास जाना ही पड़ता है, लेकिन अब जिस प्रक्रिया को लाने की बात हो रही है, उसमें अपील भी फेसलेस होगी. मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आय का मूल्यांकन किया गया और उस पर कर लगा दिया गया, लेकिन उस व्यक्ति को लगता है कि उसका मूल्यांकन गलत हुआ है, तो वह इसके लिए अपील करेगा. अभी तक अपील करने के लिए आयकर अधिकारी या कमिश्नर के पास जाना पड़ता था. अब एक नयी प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है, जहां अपील भी ऑनलाइन होगी और आपकी अपील किसी अधिकारी को सौंप दी जायेगी, लेकिन आप जान नहीं पायेंगे कि किस अधिकारी को आपकी अपील सौंपी गयी है. यही फेसलेस अपील है. चार्टर की यदि बात करें, तो इसका अर्थ होता है पारदर्शी तरीके से सभी चीजें विभाग द्वारा घोषित कर देना कि वे किसी तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से आपका मूल्यांकन करेंगे आदि. चूंकि अब कर से जुड़ी बहुत-सी प्रक्रियाएं फेसलेस हो जायेंगी, तो सब चीज ऑनलाइन ही होंगी. आप विभाग की वेबसाइट पर जायेंगे, तो वहां पर आपको सब चीजें दिख जायेंगी. चार्टर के जरिये आमतौर पर यही होने की संभावना है. चार्टर में कौन-कौन से बिंदु रखे गये हैं, यह एक अलग बात है, लेकिन चार्टर का हमेशा आशय यही होता है कि हमने सब चीज पारदर्शिता के साथ पहले से सामने रख दी है. वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि आपसे क्या अपेक्षा है और कर विभाग क्या व कैसे काम करेगा. यह भी पारदर्शिता लाने की एक प्रक्रिया है. जब भी ज्यादा पारदर्शिता लायी जाती है, तो हमेशा भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हो जाती हैं. इससे कर विभाग और करदाता, दोनों को चीजों को समझने में आसानी होगी, गलती करने की भी संभावना कम हो जायेगी. यहां किसी विशेष परिस्थिति में ही कोई गलती होगी. असल में, चार्टर करदाता और कर विभाग दोनों के लिए सीमाएं तय कर देता है. कर सुधार की बात करें, तो यह प्रक्रिया हमारे देश में बहुत समय से चल रही है. हमारे देश में समय-समय पर तरह-तरह के कर सुधार होते रहे हैं. हाल का सबसे बड़ा कर सुधार जीएसटी है. हमारे जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, उनमें से अधिकांश जीएसटी के अंतर्गत ला दिये गये हैं. इसी तरह समय-समय पर प्रत्यक्ष कर, जैसे आयकर में भी सुधार होता रहा है. यदि आप पिछले कुछ बजट को देखें, तो सरकार का विशेष फोकस करदाता की कम संख्या को लेकर रहा है. देशभर में मुश्किलन एक से डेढ़ करोड़ व्यक्ति ही कर का भुगतान कर रहे हैंय बाकी लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं. इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि सरकार को कर की दर बढ़ानी पड़ती है, लेकिन अब कोशिश यह है कि टैक्स नेक यानी कर के दायरे को और बढ़ा दिया जाये. इस कारण पारदर्शिता बढ़ेगी. पिछले कुछ समय में जो बदलाव हुए हैं, उनमें नकद भुगतान पर विशेष रूप से रोक लगाने की कोशिश की गयी है. नकद भुगतान जितना कम होगा, बैंक के माध्यम से लेन-देन उतना बढ़ जायेगा. ऐसे में आप जितने भी बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगे और उसके जरिये जो भी लेन-देन करेंगे, वह आपके बैंक के माध्यम से और आपके आधार से जुड़े होने के कारण कर विभाग की नजर में स्वतः ही आ जायेगा, क्योंकि उनके पास आपका सारा डेटा है. दूसरा, जीएसटी में तमाम तरह की क्रेडिट सुविधाएं दी गयी हैं. उदाहरण के लिए, आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और तमाम तरह की इंटरमीडिएट वस्तुओं का इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिस पर पहले से कर का भुगतान किया हुआ है, तो आप टैक्स क्रेडिट का लाभ ले सकते हैं. जैसे, आप ब्रेड बनाते हैं, तो ब्रेड से पहले कोई दूसरी कंपनी आटा बना रही है. आपने कंपनी का आटा खरीदा और उससे ब्रेड बना लिया. आटा पर यदि पहले से कुछ कर का भुगतान किया हुआ है, तो पहले से दिये गये इस कर का क्लेम करने पर आपको रिफंड मिल सकता है. मान लीजिए, मेरी फैक्ट्री है. मैंने उसके लिए काफी सारा आटा खरीदा, लेकिन उसका आधा ही दिखाया, लेकिन जिस कंपनी से मैंने आटा खरीदा था, उसने अपना टैक्स क्रेडिट क्लेम किया और घोषित किया कि उसने सौ क्विंटल आटा मुझे बेचा था, पर यहां तो मैंने पचास क्विंटल आटे पर ही कर का भुगतान किया है. इस प्रकार, इस प्रक्रिया से धीरे-धीरे पारदर्शिता आती जायेगी और जो चोरी हो रही है, वह कम हो जायेगी. यदि जीएसटी में तमाम तरह की चोरी पकड़ में आयेगी, तो आयकर विभाग को भी यह पता लगेगा कि फलां व्यक्ति ने अब तक मात्र पचास करोड़ का ही लेन-देन दिखाया था, जबकि इसने कच्चा माल ही सौ करोड़ का खरीदा था. तब उसकी आय का मूल्यांकन भी इसी के अनुसार बदलता चला जायेगा. इससे अपने आप ही यह पता लगेगा कि कौन गड़बड़ कर रहा है. इससे धीरे-धीरे पारदर्शिता की प्रक्रिया स्वतः विकसित होती चली जायेगी और इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका होगी.

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग... कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार बुमराह आठवें से खिसकर नौवें स्थान पर

नई दिल्ली | एजेंसी।

भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जिसमें शीर्ष 10 में दो अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं. मंगलवार को जारी रैंकिंग में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नौवें स्थान पर खिसक गए। कोहली 886 अंक के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा (766) और अजिंक्य रहाणे (726) भी बल्लेबाजी सूची में क्रमश- आठवें और 10वें स्थान पर कायम हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ शीर्ष रैंकिंग वाले बल्लेबाज हैं। बुमराह गेंदबाजों की रैंकिंग में एक स्थान के नुकसान से नौवें स्थान पर खिसक गए, जबकि रवींद्र जडेजा ऑलराउंडरों की सूची में तीसरे स्थान पर बरकरार हैं। साउथेम्प्टन में ड्रॉ टेस्ट के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने करियर की सर्वश्रेष्ठ पांचवीं रैंकिंग पर वापसी की, जबकि इंग्लैंड की स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन की अनुभवी तेज गेंदबाजी जोड़ी को भी फायदा हुआ है। फरवरी में करियर की सर्वश्रेष्ठ पांचवीं रैंकिंग हासिल करने वाले बाबर ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 47 रनों की बदौलत एक बार फिर यह रैंकिंग हासिल की. साउथेम्प्टन में अर्धशतक जडने वाले पाकिस्तान के आबिद अली (49) और मोहम्मद रिजवान (75) ने भी करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की। ब्रॉड दूसरे टेस्ट में 56 रन देकर चार विकेट चटकाने के बाद एक स्थान के फायदे से दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि 60 रन देकर तीन विकेट हासिल करने वाले एंडरसन दो स्थान के फायदे से 14वें स्थान पर हैं। इंग्लैंड की पारी में 28 रन देकर दो विकेट चटकाने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास दो स्थान के फायदे से आठवें पायदान पर हैं। बल्लेबाजों की सूची में इंग्लैंड के जैक क्राउली 53 रन की पारी के बाद करियर के सर्वश्रेष्ठ 81वें स्थान पर हैं। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और कप्तान जो रूट ने अपना क्रमशः सातवां और नौवां बरकरार रखा है. आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में भारत 360 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया (296) का नंबर आता है। इंग्लैंड 279 अंकों के साथ तीसरे, जबकि पाकिस्तान 153 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। चौथे

भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना, संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल वक्त की मांग

मुंबई | एजेंसी।

भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का आयोजन कोविड-19 महामारी के इस दौर में बेहद जरूरी है और हर कोई इसका आयोजन चाहता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल का आयोजन यूएई में करने का फैसला किया है। यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच खेला जाएगा।

इस तरह से इसमें 51 दिन के अंदर 60 मैच होंगे। शास्त्री ने एक वेबिनार के दौरान कहा, कोविड के इस दौर में जब आईपीएल यूएई में शुरू होगा तो आप देखेंगे कि फिर से पहले जैसा माहौल बन गया है, जिसकी बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि यूएई ने 2014 में दिखाया कि वह इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन करने में सक्षम है। शास्त्री ने कहा, यूएई में क्रिकेट के आयोजन की अनुमति देना भारत सरकार का बड़ा फैसला है।

पीएम मोदी के कहने पर भारतीय टीम में लौटेंगे धोनी

नई दिल्ली एजेंसी। महेंद्र सिंह धोनी ने भले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को लगता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व भारतीय कप्तान से अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का अनुरोध कर सकते हैं। धोनी आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने साल 2007 में पहला वर्ल्ड टी20 जीता था। इसके बाद 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके साथ ही 2010 और 2016 का एशिया कप भी भारत ने धोनी की कप्तानी में जीता था। 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद 39 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने 350 वनडे इंटरनेशनल, 90 टेस्ट और 98 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं।

रोहित शर्मा समेत चार प्लेयर खेल रत्न को नॉमिनेट, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, मरियप्पन के नाम की भी सिफारिश

नई दिल्ली | एजेंसी।

क्रिकेटर रोहित शर्मा को देश का 'राजीव गांधी खेल रत्न' मिलने जा रहा है। शर्मा का नाम इस साल खेल रत्न अवार्ड के लिए फाइनल कर लिया गया है। वह खेल रत्न पाने वाले चौथे क्रिकेटर होंगे। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को यह सम्मान मिल चुका है। रोहित के अलावा खेल रत्न के लिए पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, पैरालंपियन मरियप्पन थांगावेलु के नाम की सिफारिश भी की गई है। राष्ट्रीय पुरस्कार समिति की मंगलवार को यहां राष्ट्रीय राजधानी में एक बैठक हुई, जिसमें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चार खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की गई। रोहित ने 2019 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 648 रन बनाए थे। वहीं, विनेश, एकमात्र भारतीय महिला पहलवान हैं, जिन्होंने अब तक टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है। विनेश 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीत चुकी हैं। महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका ने 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में दो स्वर्ण पदक जीता था। पैरालंपिक खिलाड़ी मरियप्पन ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है।

भीम अवार्डी कबड्डी खिलाड़ी को सरकारी नौकरी का इंतजार

हमेशा केवल आश्वासन प्राप्त हुआ। एक फौजी की बेटी प्रियंका ने देश को गौरव के पल कई बार दिए,

नयी दिल्ली | एजेंसी।

गांव की मिट्टी में खेलते हुए देश के लिए 11 व हरियाणा के लिए 17 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी की कैप्टन व भीम अवार्डी प्रियंका पिलानिया वर्षों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही है। प्रियंका कहती हैं, देश को सोने का तगमा दिलाने के लिए दिन-रात मेहनत की, विश्व में नाम भी चमकाया बावजूद इसके सरकार की अनदेखी के कारण सरकारी का सपना पूरा नहीं हुआ। चरखी दादरी के गांव आदमपुर डाढ़ी की कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका पिलानिया ने बताया कि जब साल 2012 में कबड्डी वर्ल्ड कप हासिल किया, तो लगा कि इनाम के साथ अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी, किन्तु किसी ने पूछा तक नहीं। फिर साल 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, तो सरकार ने भीम अवार्ड से नवाजा। ऐसे में लगा कि शायद अब किस्मत में भी बदलाव हो जाये,सरकारें भी बदली और सरकारी नीति भी परन्तु अभी भी स्थिति पूर्व की ही तरह हैं। एमए इतिहास की छात्रा प्रियंका का कहना है कि तकलीफ और दुख होता है कि फर्स्ट श्रेणी की नौकरी तो दूर की बात है, चतुर्थ श्रेणी की नौकरी तक के लिए नहीं पूछा गया। हमेशा केवल आश्वासन प्राप्त हुआ। एक फौजी की बेटी प्रियंका ने देश को गौरव के पल कई बार दिए, किन्तु अपने राज्य में सम्मान की नौकरी हासिल करने के लिए आज तक भटक रही है। अभी हाल ही में पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर कबड्डी खिलाड़ी कविता की हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में उप निदेशक के पद नियुक्ति हुई तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इसी के साथ प्रियंका ने अपना दर्द बयां किया है।

बॉलीवुड

अक्षरा सिंह का तीज स्पेशल गाना 'हे नाथ दिन लौटाई' रिलीज

मुंबई - भोजपुरी सिनेमा की जानीमानी अभिनेत्री गायिका अक्षरा सिंह का तीज स्पेशल गाना 'हे नाथ दिन लौटाई' रिलीज कर दिया गया है। अक्षरा सिंह का तीज स्पेशल गाना 'हे नाथ दिन लौटाई' उनके ऑफिसियल यूट्यूब अकाउंट पर जारी किया गया है। 'हे नाथ दिन लौटाई' को अक्षरा सिंह ने खुद अपनी आवाज दी है। मनोज मतलबी ने इसके लिरिक्स बनाये हैं। अविनाश झा घुंघरू जी का म्यूजिक है। अक्षरा ने अपने इस गाने को उन महिलाओं को समर्पित किया है, जिसको पति से दुत्कार मिलता है। अक्षरा ने कहा, यह गाना सभी औरतों के लिए खास है। बात समझने की है और हमने यही इस गाने से समझाने की कोशिश भी की है। मुझे लगता है कि गाना सबको खूब पसंद आयेगी। अभी तक गाने को मिले रिस्पांस से मैं काफी खुश भी हूं। उम्मीद है कि यह गाना भी आपके आशीर्वाद और दुआ से सफलता के सर्वोत्तम शिखर पर होगी। अक्षरा के इस दर्द भरे गाने का थीम एक सामाजिक समस्या से जुड़ा है। मां-बाप की मर्जी से बेटे की शादी जब जबरदस्ती कर दी जाती है, तब वो अपनी दुल्हन को स्वीकार कर नहीं पाता है। ऐसे में उस दुल्हन की हालत क्या हो जाती है, इस गाने में अक्षरा ने यही दिखाने की कोशिश की है।

अक्षय कुमार ने असम बाढ़ पीड़ितों को दिए एक करोड़

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक करोड़ रुपये दिए हैं।अक्षय कुमार लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अक्षय ने कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान देते हुए एम केयर्स फंड में काफी रुपये दिए थे। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की भी मदद की। अब उन्होंने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अक्षय ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक करोड़ रुपए दान दिए हैं। इसके लिए असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अक्षय को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने अक्षय का शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट किया, असम बाढ़ में राहत की दिशा में एक करोड़ के अपने योगदान के लिए अक्षय कुमार का शुक्रिया। आपने हमेशा संकट के समय सहानुभूति और समर्थन दिया है। असम के एक सच्चे दोस्त के रूप में, भगवान आपको वैश्विक क्षेत्र में अपनी महिमा को ले जाने के लिए आशीर्वाद दें।

विपाशा के ब्रेक लेने वजह

बॉलीवुड की बोल्ड गर्ल और अभिनेत्री विपाशा बसु ने फिल्मों से ब्रेक लेने की वजह बतायी है। बिपाशा बसु और उनके पति करण सिंह ग्रोवर की फिल्म 'डेंजरस' हाल ही ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज हुई है। इस फिल्म के जरिए बिपाशा ने पांच साल के ब्रेक बाद वापसी की है। विपाशा ने अंतिम बार वर्ष 2015 में प्रदर्शित फिल्म 'अलोन' में काम किया था। फिलमें से ब्रेक लेने को लेकर विपाशा ने कहा कि मैं 19 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, काफी लंबा वक्त हो गया था इसलिए एक ब्रेक लेना जरूरी था। बिपाशा ने बताया कि उन्होंने 18 साल की उम्र में मॉडलिंग की शुरुआत की और फिर 19 साल की उम्र में अपना फिल्मी कॉरियर शुरू किया। इसके बाद लगातार वह फिल्में करती रहीं। लंबा वक्त हो गया था और अब शादी के बाद अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड के लिए एक ब्रेक लेना बेहद जरूरी हो गया था। विपाशा ने कहा ,मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलती हूं। लंबे ब्रेक के समय मैंने अपनी फैमिली के साथ खूब एन्जॉय किया है और अब मैं एक बार फिर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अब मैंने फिल्म 'डेंजरस' के साथ अपने अभिनय की दूसरी पारी की शुरुआत कर दी है।

कपिल के शो पर इस हफ्ते होगा डबल धमाल

दि कपिल शर्मा शो में इस वीकेंड मस्ती का अनलिमिटेड धमाल होने जा रहा है। इस बार सिंगर मीका अपने खास अंदाज में कपिल के सवालों का जवाब देते नजर आएंगे। ऐसे में कम्मो बुआ (भारती सिंह) की शरारतें भी दर्शकों को खूब गुदगुदाएंगी। इस एपिसोड में कृष्णा अभिषेक प्यारे मिट्ठी माउस बनकर इस वीकेंड अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कृष्णा का किरदार सभी को पसंद है, लेकिन इस हफ्ते वे कुछ अलग करने जा रहे हैं। मीका सिंह के साथ बिग बॉस 13 में नजर आईं एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला भी कपिल के शो में चार चांद लगाने आने वाली हैंद्ध जहां शनिवार को मीका सिंह के साथ कपिल और उनके शो के कलाकार मस्ती करते नजर आएंगे. वहीं रविवार की शाम भी खास होने वाली है। रविवार को कपिल शर्मा शो में सोनी लिव की नई वेब सीरीज योर ऑनर के कलाकार आएंगे। इसमें जिम्मी शेरगिल, मीता वशिष्ठ और वरुण बडोला शामिल होंगे। योर ऑनर वेब सीरीज की बात करें तो ये एक जज और उसके बेटे की कहानी पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे अपने बेटे को गैंगस्टर से बचाने के लिए जज अपने रिश्ते और कानून से लड़ जाता है। कोरोना के इस काल में भी कपिल शर्मा अपने शो के जरिए दर्शकों को हंसाने का काम कर रहे हैं। इन नए एपिसोड्स में भी वे फैन्स से वीडियो कॉल पर बात करते और उनकी टांग खींचते नजर आएंगे।

वरूण धवन की मां का किरदार निभाएगी नीतू सिंह

बॉलीवुड अभिनेत्री और दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह आने वाली फिल्म में वरूण धवन की मां का किरदार निभाती नजर आएंगी। ऋषि कपूर के निधन के बाद नीतू सिंह ने पहली बार फिल्म साइन की है। बताया जा रहा है कि नीतू सिंह ने राज मेहता की फिल्म के लिए हां कर दी है। इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन, कियारा आडवाणी और अनिल कपूर भी नज़र आएंगे। बताया जा रहा है कि नीतू फिल्म में वरुण धवन की मां का किरदार निभाएंगी, जबकि अनिल कपूर नीतू कपूर के पति यानी वरुण के पिता के रुप में नज़र आएंगे। यह रोमांटिक फिल्म अक्टूबर के आखिरी तक या नवंबर में फ्लोर पर आ सकती है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म नॉर्थ इंडिया की कहानी पर आधारित है और यह फिल्म गुड न्यूज का सीक्वल नहीं है। इस फिल्म की कहानी काफी अलग है। नीतू कपूर सिंह अंतिम बार वर्ष 2013 में प्रदर्शित फिल्म 'बेशर्म' में नज़र आई थीं, जिसमें रणबीर कपूर और ऋषि कपूर भी थे।

प्रियंका चोपड़ा ने पहली इंटरनेशनल फिल्म 'ईविल आई' का किया एलान

बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्माता प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पहली इंटरनेशनल फिल्म 'ईविल आई' का एलान कर दिया है।प्रियंका चोपड़ा ने जुलाई के पहले हफ्ते में अमेजन स्टूडियो के साथ कई फिल्मों की करोड़ों रुपए की डील साइन की थी। उसी ऐलान के तहत अब प्रियंका की प्रोडक्शन कंपनी परपल पेबल पिक्चर्स ने सोशल मीडिया के जरिए पहली इंटरनेशनल फिल्म 'ईविल आई' का ऐलान किया है। यह एक हॉरर फिल्म है, जो अमेजन ओरिजिनल की एंथोलॉजी फिल्म 'वेलकम टू द ब्लमहाउस' का पार्ट होगी। फिल्म का निर्देशन लॉस एंजेलिस के फिल्ममेकर्स एलन दसानी और राजीव दसानी ने किया है। प्रियंका ने बताया कि यह फिल्म अक्टूबर में आ रही है 'ईविल आई' के अलावा प्रियंका अमेजन प्राइम वीडियो के लिए एक रियटिली शो 'संगीत' का निर्माण भी कर रही हैं, जिसमें उनके पति निक जोनस भी हैं। दूसरा प्रोजेक्ट एक स्पाई ड्रामा है।

प्रशंसकों से क्या बोली, लंग कैंसर से लड़ रहे संजू की पत्नी मान्यता

बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने अपने पति 'संजू' को इतने सालों से मिले प्यार और स्नेह के लिए सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया है और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका परिवार संकट के समय विजेता बनकर उभरेगा। लंग कैंसर से जूझ रहे संजय दत्त इलाज के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले चर्चा थी कि संजय दत्त विदेश जाकर अपना इलाज कराएंगे। मान्यता ने कहा कि संजू ने अपनी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर कठिन दौर से गुजरने के दौरान आपके प्यार और सहयोग ने उन्हें बेहद हिम्मत दी है और इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। अब हमें एक और चुनौती के लिए चुना गया है और मुझे पता है, यही प्यार और स्नेह उन्हें इस मुश्किल वक्त से निकालने में भी मदद करेगा। मान्यता दत्त ने कहा कि एक परिवार के रूप में, हमने सकारात्मकता और ग्रेस के साथ इसका सामना करने का फैसला किया है। हम मुस्कान के साथ, अपने जीवन को संभव तरीके से सामान्य बनाने जा रहे हैं, क्योंकि यह एक कठिन लड़ाई होने के साथ-साथ एक लंबा सफर भी है। हमें किसी नकारात्मकता के बिना, संजू के लिए ऐसा करने की जरूरत है। इस मुश्किल समय में दुर्भाग्य से मैं अपने होम क्वारंटीन के कारण अस्पताल में उनके साथ खड़े रहने में असमर्थ हूं। जो अब बस कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा।

राज्यों ने अब तक ढाई करोड़ प्रवासियों को मुफ्त अनाज वितरित किया

● ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास न तो केन्द्र और न ही राज्य सरकार का कोई राशन कार्ड है। योजना के तहत राज्यों को अनाज वितरण के लिए 31 अगस्त का समय दिया गया।

नई दिल्ली | एजेंसी।

मंत्रालय ने कहा है कि यदि प्रवासी मजदूर अपने मूल निवास वाले राज्यों में लौट गए हैं तो वह पहले से ही राष्ट्रीय खाद्य सरक्षा कानून

राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अब तक आठ करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 2.51 करोड़ प्रवासी मजदूरों को ही मुफ्त अनाज वितरित किया है। केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अनाज का कम वितरण यह बताता है कि प्रवासी कामगारों की वास्तविक संख्या कम थी। मंत्रालय ने कहा है कि यदि प्रवासी मजदूर अपने मूल निवास वाले राज्यों में लौट गए हैं तो वह पहले से ही राष्ट्रीय खाद्य सरक्षा कानून (एनएफएसए) या फिर राज्य की राशन कार्ड योजना के तहत पहले से ही खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत कम लोगों को लाभ मिलने को योजना का कमजोर प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि आठ करोड़ प्रवासी का आंकड़ा वास्तविक लक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने मई मध्यम में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को पांच किलो खाद्यान्न और एक किलो चना मुफ्त वितरित करने की घोषणा की थी। यह सुविधा मई और जून दो माह के लिए आठ करोड़ प्रवासियों के लिए शुरू की गई। ऐसे प्रवासी मजदूर जिनके पास न तो केन्द्र और न ही राज्य सरकार का कोई राशन कार्ड है। योजना के तहत राज्यों को अनाज वितरण के लिए 31 अगस्त का समय दिया गया। केन्द्र ने इस योजना के तहत राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों को दो माह के लिए 8 लाख टन अनाज का आवंटन किया, लेकिन राज्यों ने इसमें से केवल 6.38 लाख टन अनाज ही उठाया। खाद्य मंत्रालय ने कहा, 17 अगस्त तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 6.38 लाख टन अनाज में से राज्य अथवा संघ शासित प्रदेशों ने आत्मनिर्भर भारत याजना के तहत पहचान किए गए प्रवासियों और रास्ते फंसे प्रवासियों को 2.49 लाख टन (39 प्रतिशत) अनाज का ही वितरण कर पाए। मंत्रालय का कहना है कि यह वितरण हालांकि 31 अगस्त तक जारी रहेगी इसलिए हो सकता है कि कुछ और प्रवासियों को इस मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ मिल जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस योजना के तहत मुफ्त अनाज वितरण के अलावा कुछ राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर ने मार्च 2020 के बाद बिना राशन कार्ड वाले लोगों नये राशन कार्ड भी जारी किए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान 60- 70 लाख अतिरिक्त लोग भी योजना के दायरे में आये हैं। ये लाग राज्य से बाहर होने के कारण पहले कार्ड धारक नहीं थे वापस लौटने पर उन्हें नये राशन कार्ड प्रापत हो गए। इस संख्या को यदि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लाभ पाने वाले 2.51 करोड़ प्रवासियों की संख्या में जोड़ दिया जाए तो मासिक आधार पर लाभ पाने वालों की वास्तविक संख्या 3.81 करोड़ तक पहुंच जाएगी।

एक नजर.....

आरईसी लिमिटेड ने लांच की कॉफी टेबल बुक

नई दिल्ली, आरईसी लिमिटेड ने अपने 51वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजीव कुमार गुप्ता की उपस्थिति में कॉफी टेबल बुक लॉन्च की। अपने शानदार 51 सालों में, आरईसी लिमिटेड ने साबित कर दिया है कि यह भारत के प्रमुख एनबीएफसी और प्रीमियर पावर फाइनांसिंग उद्यमों में से एक है, जबकि अपने शेयरधारकों को समृद्ध लाभांश का भुगतान करता है।

इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में वित्तपोषण परियोजनाएं शामिल हैं; विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में उत्पादन, पारेषण, वितरण परियोजनाएं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।

तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का करेगी निजीकरण

नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक, निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को किराए पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अहम फैसलों के बारे में बताया। ये मंजूरी सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दी है। यानी ये तीनों एयरपोर्ट अब निजी कंपनियां चलाएंगी। इस बात की चर्चा पहले से थी कि मोदी सरकार कुछ एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में दे सकती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रबंधित छह और हवाई अड्डों को निजी हाथों में सौंपने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की उम्मीद पहले ही लगाई ज रही थी। एएआई के निदेशक मंडल ने अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिचि हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी हाथों में सौंपने की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को नागरिक उड्डयन क्षेत्र के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए प्रक्रिया तेज कर तीन महीने के भीतर निविदा जारी करने का निर्देश दिया था। कोविड-19 के कारण एएआई ने इस साल जून में अडाणी को इन तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ का प्रबंधन संभालने के लिये तीन और महीने दिए। इसका मतलब है कि उसे इनका प्रबंध सभालने के लिए 12 नवंबर तक का समय है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र के दूरदर्शी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में स्थित तीन अन्य हवाई अड्डों को पीपीपी आधार पर पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन हवाई अड्डों पर पीपीपी से न सिर्फ हवाई यात्रियों को कुशल और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी, बल्कि राजस्व बढ़ाने में भी एएआई को मदद मिलेगी। इससे एएआई टियर- और टियर शहरों में अधिक हवाई अड्डों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। पुरी ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष कुछ और हवाई अड्डों के निजीकरण का एक प्रस्ताव रखेगा।

बेकारों की लॉकडाउन पीढ़ी बनने का खतरा

नई दिल्ली, देश में कोविड-19 महामारी के कारण 41 लाख युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। इसमें निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सर्वाधिक प्रभावित हुए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की संयुक्त रिपोर्ट में यह कहा गया है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटना शीर्षक से आईएलओ-एडीबी की आज जारी रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में 41 लाख युवाओं के रोजगार जाने का अनुमान है। सात प्रमुख क्षेत्रों में से निर्माण और कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक लोगों के रोजगार गए हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को भी तगड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के अनुसार संकट के कारण तत्काल 15 से 24 साल के युवा 25 और उसे अधिक उम्र के लोगों के मुकाबले ज्यादा प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं आर्थिक और सामाजिक लागत के हिसाब से जोखिम दीर्घकालिक और व्यापक है। आईएलओ-एडीबी रिपोर्ट युवा और कोविड-19 पर वैश्विक सर्वे के क्षेत्रीय आकलन पर आधारित है। अनुमान विभिन्न देशों में उपलब्ध बेरोजगारी के आंकड़े के आधार लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में महामारी के दौरान कंपनी के स्तर पर दो तिहाई प्रशिक्षण (एप्रेन्टिसशिप) पर असर पड़ा। वहीं तीन चौथई इंटर्नशिप पूरी तरह से बाधित हुए हैं। रिपोर्ट की प्रमुख लेखिका और आईएलओ क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण इकाई प्रमुख सारा एल्डर ने कहा, कोविड-19 संकट के बाद से जो चुनौतियां युवाओं के लिए थीं, वह और बढ़ गई हैं। अगर इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, एक लॉकडाउन पीढ़ी सृजित होने का खतरा है

जिसे इस संकट का भार कई साल तक महसूस करना पड़ सकता है।%

इसकी सेवाएं देश के करीब 20,000 स्थानों में उपलब्ध हैं।

620 करोड़ में खरीदा नेटमेड्स

● इस साझेदारी के जरिये हम रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के ग्राहकों का दायरा और व्यापक तथा विशाल बनाने में सक्षम होंगे।' नेटमेड्स के संस्थापक और सीईओ प्रदीप डाढा ने सौदे पर कहा, इस संयुक्त मजबूती से हम ईकोसिस्टम में प्रत्येक के लिए मूल्यवान सेवाएं को देने में सक्षम होंगे।

नयी दिल्ली | एजेंसी।

रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड(आरआरवीएल) ने चेन्नई की विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहायक इकाइयों में बहुमत हिस्सेदारी 620 करोड़ रुपये में खरीदी है। विटालिक और उसकी सहायक इकाइयों को सामूहिक तौर पर नेटमेड्स के रूप में जाना जाता है। यह सौदा नगद लेनदेन में हुआ है।आरआरवीएल एशिया के सबसे बड़े अमीर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की अनुषंगी इकाई है।आरआईएल के अनुसार सौदे में उसने विटालिक में 60 प्रतिशत अंशधारिता खरीदी है। रिलायंस ने विटालिक की अनुषंगी ट्रेसरा हेल्थ, नेटमेड्स मार्केट प्लेस और डाढा फार्मा वितरण का शत प्रतिशत स्वामित्व खरीदा है।टालिक सौदे पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रिलायंस की खुदरा कारोबार निदेशक ईशा अंबानी ने कहा, यह सौदा हमारी उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जिसमें हमने देश में प्रत्येक व्यक्ति तक डिजिटल पहुंच की बात कही है। नेटमेड्स के साथ आने से रिलायंस रिटेल अच्छी गुणवत्ता और किफायती हेल्थकेयर उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करा पाने में और मजबूत होगी। नेटमेड्स ने जिस तरह बहुत कम समय में देशभर में डिजिटल फ्रेंचाइजी का विस्तार किया, उसने हमें प्रभावित किया हैं। विटालिक की स्थापना 2015 में हुई थी और उसकी सहायक कंपनियां फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और कारोबार सहयोग सेवा में हैं । इसकी अनुषंगी के माध्यम से ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार नेटमेड्स के नाम से संचालित किया जाता है, जो उपभोक्ताओं को फार्मासिस्ट से जोड़ती है और सीधे उनके द्वार तक दवाएं, न्यूट्रीशनल और वेलनेस उत्पाद पहुंचाती है।रिलायंस रिटेल ने इस वर्ष मई में नेटमेड्स के साथ किराना सामान पहुंचाने के लिये समझौता किया था। नेटमेड्स एक ई-फार्मा पोर्टल है जिसके द्वारा प्रिस्क्रिप्शन आधारित और ओवर-द-काउंटर दवाएं और अन्य हेल्थ उत्पादों की बिक्री की जाती है। इसकी प्रर्वतक चेन्नई की डाढा फार्मा है।इस सौदे से देश के ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू होने की प्रबल संभावना है । ऐमजॉन पहले ही उतर चुका है जबकि फ्लिपकार्ट भी इस क्षेत्र में उतरने की तैयारी में है।

किसानों के लिए खुशखबरी, 10 रुपये क्विंटल बढ़ा गन्ने का दाम

नई दिल्ली | एजेंसी।

केन्द्र सरकार ने बुधवार को गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) दाम 10 रुपये बढ़ाकर 285 रुपये क्विंटल करने को मंजूरी दे दी। यह दाम गन्ने के अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाले नए विपणन सत्र के लिये तय किया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में गन्ने का 2020- 21 (अक्टूबर-सितंबर) विपणन वर्ष के लिए एफआरपी दाम 10 रुपये क्विंटल बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सीसीईए ने खाद्य मंत्रालय के इस संबंध में दिये गये प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने अगले विपणन सत्र के लिए गन्ने का एफआरपी 275 रुपये से बढ़ाकर 285 रुपये क्विंटल करने का प्रस्ताव दिया था। सीएसीपी सरकार को प्रमुख कृषि उत्पादों के दाम को लेकर सलाह देने वाली सांविधिक संस्था है।

एफआरपी को गन्ना (नियंत्रण) आदेश 1966 के तहत तय किया जाता है। यह गन्ने का न्यूनतम मूल्य होता है जिसे चीनी मिलों को गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान करना होता है। सरकार का अनुमान है कि चालू विपणन सत्र

में गन्ने का कुल उत्पादन 280 से 290 लाख टन रह सकता है। गन्ने का चालू विपणन सत्र अगले महीने समाप्त हो रहा है। पिछले साल 2018- 19 में देश में 331 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की खेती में कमी आने से चालू विपणन सत्र में उत्पादन कम रहने का अनुमान है।

अटल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर

नई दिल्ली, सवांददाता। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की नवीनतम अटल रैंकिंग (एआरआईआईए) में राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) के बीच शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी मद्रास के बाद इस श्रेणी में दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर क्रमशः आईआईटी बंबई, आईआईटी दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएस) बेंगलूरु और आईआईटी खडगपुर शामिल हैं। आईआईटी बंबई के निदेशक शुभाशिष चौधरी ने कहा कि आईआईटी बंबई नवोन्मेष और उद्यमशीलता पर काफी जोर देता है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए काफी मेहनत करता है कि अनुसंधान का परिणाम उत्पादों के रूप में सामने आए जिससे देश को लाभ हो। दूसरी ओर संस्थान के डीन (शोध एवं विकास) मिलिंद अत्रे ने कहा कि आईआईटी बंबई उद्योग-शैक्षिक सहजीविता के विकास के लिए कड़ा श्रम करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रयोगशालाओं में विकसित नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी बड़े स्तर पर समाज तक पहुंचे। अपने दूसरे संस्करण में एआरआईआईए ने सामान्य रूप से वैश्विक स्तर पर उपयोग किए जाने वाले मुख्यतः नवोन्मेष से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग पर विचार किया है। एआरआईआईए का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवोन्मेष और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय संस्थानों को अपने सोच-विचार में बदलाव और पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है। इसके अलावा एआरआईआईए का उद्देश्य भविष्य के विकास के लिए संस्थानों के वास्ते दिशानिर्देश तैयार करना भी है ताकि उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और नवोन्मेष के मोर्चे पर आगे लाया जा सके। इस रैंकिंग में छह श्रेणियों के अंतर्गत नवोन्मेष के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सूची शामिल है। राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/सीएफटी के अलावा अन्य पांच श्रेणियों में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालय, निजी या स्व-वित्तपोषित कॉलेज और विश्वविद्यालय तथा विशेष रूप से महिलाओं के उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त तीन शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल हैं - रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीटी), पंजाब विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जबकि नवोन्मेष के लिए शीर्ष तीन निजी या स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में सबसे ऊपर है - कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ओडिशा और इसके बाद स्थान आता है एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नोलॉजी तथा और वेल्होर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु का। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों/संस्थानों में पुणे स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

इसके बाद कर्नाटक के पीईएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तथा कोयंबत्तूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान रहा।

निजी या स्व वित्तपोषित कॉलेजों/संस्थानों की श्रेणी में एसआर इंजीनियरिंग कॉलेज, तेलंगाना का सर्वोच्च स्थान रहा। इसके बाद जीएच

मोदी सरकार जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का करेगी निजीकरण

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक, निजी भागीदारी के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों को किराए पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अहम फैसलों के बारे में बताया। ये मंजूरी सरकार ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दी है। यानी ये तीनों एयरपोर्ट अब निजी कंपनियां चलाएंगी। इस बात की चर्चा पहले से थी कि मोदी सरकार कुछ एयरपोर्ट्स को निजी हाथों में दे सकती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा प्रबंधित छह और हवाई अड्डों को निजी हाथों में सौंपने संबंधी प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने की उम्मीद पहले ही लगाई ज रही थी। एएआई के निदेशक मंडल ने अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिचि हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत निजी हाथों में सौंपने की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई को नागरिक उड्डयन क्षेत्र के मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इन हवाई अड्डों के निजीकरण के लिए प्रक्रिया तेज कर तीन महीने के भीतर निविदा जारी करने का निर्देश दिया था। कोविड-19 के कारण एएआई ने इस साल जून में अडाणी को इन तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ का प्रबंधन संभालने के लिये तीन और महीने दिए। इसका मतलब है कि उसे इनका प्रबंध सभालने के लिए 12 नवंबर तक का समय है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र के दूरदर्शी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में स्थित तीन अन्य हवाई अड्डों को पीपीपी आधार पर पट्टे पर देने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन हवाई अड्डों पर पीपीपी से न सिर्फ हवाई यात्रियों को कुशल और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी, बल्कि राजस्व बढ़ाने में भी एएआई को मदद मिलेगी। इससे एएआई टियर- और टियर शहरों में अधिक हवाई अड्डों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। पुरी ने इससे पहले मंगलवार को कहा था कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष कुछ और हवाई अड्डों के निजीकरण का एक प्रस्ताव रखेगा।

एजीआर वसूली में अड़चन नहीं

मुंबई | एजेंसी।

दूरसंचार कंपनियों से बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की वसूली पर अपने रुख को दोहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि शुल्क की वसूली की राह में किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या नहीं आएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि कंपनियों द्वारा स्पेक्ट्रम शुल्क को परिचालन शुल्क के तौर पर नहीं देखा जा सकता है क्योंकि रेडियो तरंगें परिचालन के आधार पर दी गई हैं। मौजूदा समय में राजस्व साझेदारी की व्यवस्था है, ऐसे में स्पेक्ट्रम बकाया को परिचालन बकाया नहीं माना जा सकता है। रिलायंस जियो की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने स्पष्ट किया कि कंपनी ने अपना एजीआर बकाया चुका दिया है, साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के स्पेक्ट्रम के साझा इस्तेमाल से अर्जित राजस्व पर बनने वाले शुल्क का भी भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा कंपनी ने दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देश के मुताबिक स्पेक्ट्रम साझेदारी के लिए 0.5 फीसदी अतिरिक्त एसयूसी (स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क) का भी भुगतान किया है। साल्वे ने कहा कि जियो ने एजीआर मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर 195 करोड़ रुपये अदा किए हैं। शीर्ष अदालत ने सभी दिवालिया कंपनियों से स्पेक्ट्रम साझेदारी का ब्योरा मांगा था और कहा था कि रिलायंस जियो पिछले चार साल से आरकॉम के स्पेक्ट्रम का उपयोग कर रही है तथा एजीआर बकाये की उस पर देनदारी बनती है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि अदालत एजीआर बकाये का भुगतान 20 साल में करने की अनुमति नहीं दे सकती है क्योंकि संभव है कि इतने लंबे समय में कुछ कंपनियां दिवालिया हो जाए। अदालत के इस फैसले से वोडाफोन आइडिया के परिचालन पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं क्योंकि कंपनी कई बार कह चुकी है कि वह बकाया चुकाने की स्थिति में नहीं है और इसकी वजह से उसे कारोबार समेटना पड़ सकता है। केएस लीगल ऐंड एसोसिएट्स की मैनेजिंग पार्टनर सोनम चांदवानी ने कहा, एजीआर भुगतान की समयसीमा का मसला अब भी अनिश्चित है, ऐसे में दूरसंचार क्षेत्र की चिंता भी बनी हुई है। अगर शीर्ष अदालत 10 साल में भुगतान करने की अनुमति का निर्णय करती है तो यह कर्ज में दबी वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस तरह के व्यय का भुगतान करने के लिए शुल्क दरों में इजाफा करना होगा, लागत घटानी होगी और इक्विटी पूंजी निवेश करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर अदालत भुगतान के लिए 15 साल की समयसीमा तय करता है तो वोडा-आइडिया की मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। 14 अगस्त को अदालत ने आरकॉम और एयरसेल सहित दिवालिया दूरसंचार कंपनियों के स्पेक्ट्रम का उपयोग करने वाले दूरसंचार ऑपरेटरों का ब्योरा मांगा था। 10 अगस्त को अदालत ने केंद्र सरकार को आरकॉम सहित सभी दिवालिया दूरसंचार फर्मों से एजीआर बकाये की वसूली के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया था।

सस्ता हुआ सोना, चांदी के भाव में भारी गिरावट

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने-चांदी की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखने को मिल रही है। सर्राफा बाजार में सोना जहां 421 रुपये सस्ता हुआ है वहीं चांदी के भाव में भारी गिरावट आई है। बुधवार को देशभर के सर्राफा बाजारों में सोने का हाजिर भाव 53424 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। बाद में यह 421 रुपये प्रति 10 ग्राम के नुकसान के साथ 53994 रुपये पर बंद हुई। आज चांदी 2863 रुपये गिरकर 67135 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खुली और 2926 रुपये सस्ती होकर 67072 के स्तर पर बंद हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 640 रुपये की गिरावट के साथ 54,269 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 54,909 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी को बिकवाली दबाव का सामना करना पड़ा और इसकी कीमत भी 3,112 रुपये की गिरावट के साथ 69,450 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 72,562 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, %%अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) के बैठक के ब्यौरे के जारी होने के पहले बुधवार को डॉलर सूचकांक में सुधार देखने को मिला जिससे सोने का आरंभिक लाभ कुछ कम हो गया। वैश्विक बाजार में सोने का भाव कमजोरी के रुख के साथ 1,988 डॉलर प्रति औंस था जबकि चांदी का भाव अपरिवर्तित रुख के साथ 27.43 डॉलर प्रति औंस था। अमेरिकी डॉलर में आई मज़बूती के चलते विदेशी बाजार में सोना सस्ता हो गया है। बुधवार को सोने की कीमतें 2000 डॉलर प्रति औंस के नीचे आ गई है। इसके चलते भारतीय बाजारों में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतें गिर गईं। वायदा बाजार में बुधवार को सोना 0.67 फीसद की गिरावट के साथ 53,210 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया।

कंचन उजाला
हिंदी दैनिक
स्वामी नमोकंचन कार्पोरेट सर्विसेस (एल.एल.पी) के लिए प्रकाशन, मुद्रक व संपादक कंचन सोलंकी द्वारा उमाकान्ती ऑफसेट प्रेस, ग्राम डेहवा पोस्ट मोहनलाल गंज लखनऊ से मुद्रित एवं 61/18 चुटकी भण्डार हुसैनगंज लखनऊ से प्रकाशित।
संपादक- कंचन सोलंकी
TITLE CODE- UPHIN48974
Mob: 8896925119, 9695670357
Email: kanchansolanki397@gmail.com

नोटः समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारो एवं लेखों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नही। समस्त विवादो का निस्तारण लखनऊ न्यायालय के अधीन होगा।